राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

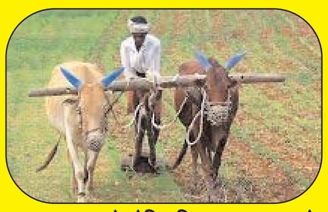

गुजरात सरकार ने घोषित किया 10,000 करोड़ का मुआवजा पैकेज किसानों को मिलेगी राहत

उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन 9 नवंबर, 2025 को कर्नाटक का दौरा करेंगे

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 309 | रायपुर | रविवार 09 नवंबर 2025 | विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

करूर भगदड़ मामला : मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, टीवीके नेता की मुश्किलें बरकरार

चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह याचिका तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। घटना कुछ महीने पहले करूर में TVK द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, भीड़ अचानक बेकाबू हो गई और अफरा-तफरी में कई लोग कुचल गए।

जम्मू-कश्मीर : घुसपैठ विफल, ऑपरेशन पिंपल में 2 आतंकवादी ढेर

श्रीनगर एजेंसी। भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन पिंपल के तहत दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया। अब इलाके की तलाशी की जा रही है।

बिहार में पीएम मोदी की हुंकार

जहां होगी रंगदारी, नहीं चलेगी दुकानदारी

पश्चिम चंपारण : संवाददाता

बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि- जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित और पीड़ित बेहाल होता है. जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं. जहां गुंडाराज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार और कारोबार ठप्प पड़ जाता है. पीएम मोदी ने इस दौरान नीतीश सरकार के काम बताए. साथ ही लोगों से वोट के लिए अपील की.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि- यहां बिहार के नौजवानों ने, महिलाओं ने, गरीब भाई-बहनों ने, मध्यम वर्ग ने, किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर NDA के समर्थन में चुनाव प्रचार खुद संभाल लिया. मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव NDA का कोई नेता नहीं, बल्कि बिहार की जनता ये चुनाव लड़ रही है. अपने पूरे चुनावी अभियान के दौरान मैंने देखा है कि एक रैली दूसरी रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती थी, एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते गए. पहले चरण के मतदान में भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं, देश आजाद हुआ तब से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मैंने बिहार के सपनों और संकल्पों को लेकर इस चुनाव अभियान में व्यापक चर्चा की है. हृष्ठ की डबल इंजन सरकार ने क्या किया है और आगे क्या करने जा रही है, अपना काम और भविष्य का रोडमैप हमने बिहार की जनता के सामने रखा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर वायरल बच्चे का भी किया जिक्र :

पीएम मोदी ने कहा कि- ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित और पीड़ित बेहाल होता है. जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं. जहां गुंडाराज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार और कारोबार ठप्प पड़ जाता है. आपने नीतीश जी के नेतृत्व में NDA का सुशासन देखा है, शांति देखी है, बिहार के लोगों ने सुकून पाया है. लेकिन, इसको जंगलराज से बचाए रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है. बिहार को तो अभी विकास की नई-नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है. मैं RJD की रैली का एक वीडियो देख रहा था. उसमें मीडिया वाले एक बच्चे से सवाल पूछते हैं कि बेटा तू लालटेन वालों की रैली में क्यों आया है. तो वो छोटा सा बच्चा भी माथा ऊंचा करके कहता है कि RJD सरकार रंगदार बनाती है और मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं.

राजद पर जमकर हमला बोला

बिहार ने सामाजिक न्याय की परिभाषा देश को दी है. अब बिहार समृद्ध भारत का, विकसित भारत का नया उदाहरण बनेगा. इसके लिए मैं आज बेतिया का, चंपारण का, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथियों के लिए मांगने आया हूं. बेतिया ने, चंपारण ने RJD और कांग्रेस के जंगलराज का सबसे डरावना रूप देखा है. जंगलराज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठैतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था. आए दिन यहां हत्याकांड होते थे, बहन-बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था. ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित और पीड़ित बेहाल होता है. जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं. जहां गुंडाराज होता है, वहां दुकानदारी चौपट हो जाती है, व्यापार और कारोबार ठप्प पड़ जाता है।

पीएम मोदी ने चार वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, अब फिरोजपुर से दिल्ली का सफर होगा 6 घंटे 40 मिनट में तय

संवाददाता वाराणसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद रहे। पीएम के हरी झंडी दिखाते ही यात्रियों ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाए। उनके स्वागत में काशीवासियों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को बनारस स्टेशन से चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ट्रेन में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों से संवाद करेंगे। विशेषज्ञों की मानें तो बनारस से खजुराहो जाने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस कई मायनों में खास बन गई है। एक ओर जहां इस ट्रेन के साथ 8 का मूलांक जुड़ा है, वहीं आध्यात्मिक रूप से भी इस ट्रेन का संचालन महत्वपूर्ण है। पीएम ने चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। वहीं आपको बता दें कि फिरोजपुर से दिल्ली का सफर वंदे भारत में 6 घंटे 40 मिनट का होगा। वहीं इससे पहले सबसे तेज चलने वाली ट्रेन पंजाब मेल में 7 घंटे 20 मिनट लगते थे। बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा।

संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा, कई अहम बिलों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली. संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी है. इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है. किरन रिजिजू ने बताया कि शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार इस सत्र में देश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने और जनता से जुड़े कानूनों को पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. बताया जा रहा है कि इस सत्र में तीन से चार नए बिल पेश किए जा सकते हैं, जिनमें चुनाव सुधार, न्यायिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और नागरिकों की सुविधा से जुड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, कुछ पुराने विधेयकों पर भी चर्चा और पारित होने की उम्मीद है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और यहां पर हर विषय पर सार्थक बहस होनी चाहिए ताकि देश के विकास के लिए ठोस निर्णय लिए जा सकें. संसद का यह सत्र लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों से पहले का अंतिम या अंतिम से पहले सत्र हो सकता है।

दुनिया को अप्रतिम स्वाद से परिचित कराना भी हमारा दायित्व : मुख्यमंत्री योगी ने की खास अपील

लखनऊ ,एजेंसी।

राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी% के रूप में चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से एक जिला-एक व्यंजन से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दुनिया को अप्रतिम स्वाद से परिचित कराना भी हमारा दायित्व है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक संदेश में कहा, राजधानी लखनऊ को यूनेस्को ने %क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी% के रूप में चुना है। व्यंजन बनाने में रचनात्मकता के लिए मिली यह मान्यता लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विविधता से भरे खान-पान का वैश्विक सम्मान है। प्रदेश का हर जनपद, अपने अनूठे स्वाद से संस्कृति, गौरव और इतिहास को जीवंत करता है। लखनऊ की चाट, बनारस की मलइयो, मेरठ की गजक, बांदा का सोहन हलवा, इटावा के मट्ठे के आलू, बागपत की बालूशाही, आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, मुरादाबादी दाल और खुर्जा की खुरचन का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह %स्वादिष्ट सूची बहुत लंबी है। हर व्यंजन का अपना अलग स्वाद है, अपना गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वान करते हुए कहा कि आप अपने आसपास स्वाद के संसार की यात्रा पर निकलकर या घर में ही बने व्यंजनों के साथ चित्र या वीडियो लें। इसे %एक जिला-एक व्यंजन% के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। सीएम योगी ने कहा कि अपने भोजन और व्यंजनों के प्रति यह प्रेम, हमारी समृद्ध खान-पान परंपरा को देश और दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाकर पर्यटन की नई तरंग का सेतु बनेगा।

यूनेस्को ने 31 अक्टूबर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (यूसीसीएन) में इस साल 58 नए शहरों को शामिल करने के एक हिस्से के रूप में लखनऊ को %क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी% का दर्जा देने की घोषणा की। 2019 में हैदराबाद के नाम के बाद लखनऊ यूसीसीएन की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है।

PFI पर ईडी का शिकंजा, 67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

एजेंसी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित संगठन पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) की 67 करोड़ रुपये की और संपत्ति जब्त की है। जब्त की गई संपत्तियां केरल के विभिन्न इलाकों में फैली हुई है। इन संपत्तियों को अवैध तरीके से जुटाए गए धन से खरीदे जाने के सबूत मिलने के बाद ईडी ने इन्हें जब्त करने का फैसला किया है। इसके पहले ईडी पीएफआइ की 62 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीएफआइ ने अपनी आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए देश-विदेश से बड़ी मात्रा में फंड इकट्ठा किया था। इन्हें विभिन्न ट्रस्टों में रखा गया था।

98 साल के हुए लाल कृष्ण आडवाणी, मिलने के लिए घर पहुंचे पीएम मोदी;

एजेंसी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी शनिवार को 98 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें जन्मतिथि पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लालकृष्ण आडवाणी जी को उनकी जन्मतिथि पर बधाई। दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से संपन्न आडवाणी जी का जीवन भारत की प्रगति को मजबूत करने के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने सदैव निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों की भावना को अपनाया है।

विदेश | दिक्कतों की वजह से वीजा देने से मना भी किया जा सकता है

यूएस में खास बीमारी वालों को नहीं मिलेगी एंट्री, वीजा नियमों में बदलाव

न्यूयॉर्क ,एजेंसी

डायबिटीज और कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए अमेरिकी वीजा पाना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वीजा नीति में कुछ बदलाव किए हैं। इसके अनुसार हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर, मोटापा और मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों को अमेरिकी वीजा के लिए मना किया जा सकता है।

ट्रंप सरकार की ओर से गुरुवार को एक निर्देश जारी किया गया, जिसके अनुसार अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों को हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ जैसी दिक्कतों की वजह से वीजा देने से मना भी किया जा सकता है। अमेरिका के केएफएफ हेल्थ न्यूज के अनुसार संबंधित विभाग को लगता है कि इन बीमारियों से ग्रसित लोग दूसरों के लिए बोझ बन सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी संसाधनों पर भी इसका बुरा असर होगा। इसलिए अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास को ये निर्देश दिया गया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ये दिशानिर्देश दोनों दूतावास को केबल के जरिए भेजा गया। हालांकि, अमेरिकी वीजा के लिए पहले भी हेल्थ कंडीशन की जानकारी ली जाती थी, लेकिन अब नए दिशा निर्देश के बाद इस प्रक्रिया में भी बदलाव होंगे।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केबल में कहा कि आपको आवेदक के स्वास्थ्य पर विचार करना होगा। कुछ मेडिकल कंडीशन, जिनमें हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ कंडिशन समेत अन्य बीमारियां शामिल हैं, इनके लिए लाखों डॉलर की देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।

इसके साथ ही वीजा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह आकलन करें कि जिस शख्स ने वीजा का आवेदन किया है, वह अपने इलाज का खर्च उठाने में सक्षम है या नहीं।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न

दोनों पक्षों ने शीघ्र, संतुलित और व्यापक व्यापार समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की

पीआइबी

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफ्टीए) पर चौथे दौर की वार्ता आज ऑकलैंड और रोटोरुआ में संपन्न हुई। दोनों पक्षों के बीच पांच दिनों तक रचनात्मक और दूरदर्शी चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री श्री टॉड मैक्ले ने इस दौर में हुई स्थिर प्रगति की सराहना की और एक आधुनिक, व्यापक और भविष्योन्मुखी एफ्टीए की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग और उत्पत्ति के नियमों सहित प्रमुख क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा की। इन चर्चाओं में आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और एक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने की साझा महत्वाकांक्षा परिलक्षित हुई जो लचीले, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा दे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत वैश्विक समृद्धि और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान देने वाली गहरी आर्थिक साझेदारियों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफ्टीए) से व्यापार प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि, निवेश संबंधों में गहनता, आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता और दोनों देशों के व्यवसायों के लिए बेहतर पूर्वानुमान और बाज़ार पहुँच सुनिश्चित होने की उम्मीद है। जारी चर्चाएं प्रक्रिया में तेजी लाने तथा समझौते को शीघ्र, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभप्रद रूप से संपन्न करने की दिशा में काम करने के दोनों देशों के साझा संकल्प को प्रतिबिंबित करती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूज़ीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो लगभग 49 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि दर्शाती है। प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा और सेवाओं जैसे सेक्टरों में और अधिक संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद है, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

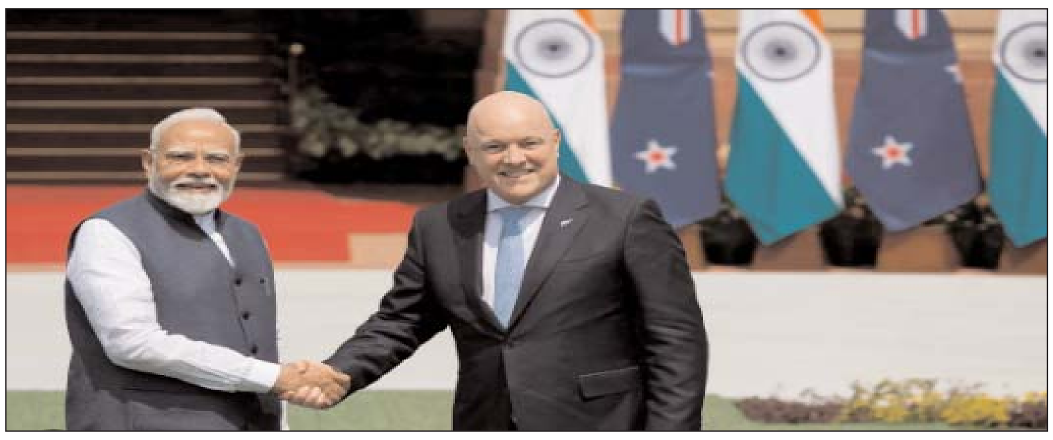

दोनों पक्षों ने अंतर-सत्रीय कार्य के माध्यम से गति बनाए रखने तथा भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर शीघ्र सहमति की दिशा में आगे बढ़ने के साझा संकल्प के साथ सभी अध्यायों में विस्तृत चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर तिलमिलाया तालिबान, कहा - सीमा पर शांति अब मुश्किल!

काबुल एजेंसी।

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। सीमा क्षेत्र पर बढ़ती झड़पों और गोलीबारी को लेकर तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी उकसाने वाली हरकतें बंद नहीं कीं, तो हालात और बिगड़ सकते हैं।

तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ओर से बार-बार की जा रही गोलाबारी और सीमा उल्लंघन से दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की हरकतों से शांति कायम नहीं रह सकती। अफगानिस्तान अपने नागरिकों और सीमा की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है।

जानकारी के अनुसार, हाल के दिनों में अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा (ड्यूरंड लाइन) पर कई बार गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें दोनों ओर से नागरिकों को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान ने दावा किया है कि सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहीं तालिबान ने इसे झूठा आरोप बताते हुए पाकिस्तान की सेना को ही जिम्मेदार ठहराया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पुराना सीमा विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। यह वही इलाका है जहां पिछले कई वर्षों से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिनसे पाकिस्तान को सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ में सड़कों के सुधार कार्य में तेजी

सरगुजा जिले में 195 किमी लंबाई में बी.टी. पैच रिपेयर कार्य प्रगति पर

रायपुर। राज्य सरकार के सुगम और सुरक्षित सड़कों वाले छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क मरम्मत और सुधार कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में सरगुजा जिले में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) संभाग अम्बिकापुर द्वारा कुल 30 मार्गों पर 195 किलोमीटर लंबाई में बी.टी. पैच रिपेयर कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन कार्यों के लिए राशि 654.85 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी 30 मार्गों को 6 समूहों में विभाजित कर निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा सभी कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। अब तक लहपटरा-बेलखरिखा, जमगला एप्रोच, अमगसी-चैनपुर, टपरकेला-धनपुरी, जरहाडांड़-मुन्दाराडांड़, तथा मेण्ड्रा-हरिहरपुर शिवपुर-करजी मार्गों पर बी.टी. पैच रिपेयर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वर्तमान में अम्बिकापुर-प्रतापपुर, केदमा-बनकेसमा, एवं दरिमा-बड़ेदमाली-लखनपुर मार्गों पर कार्य तेजी से जारी है। अब तक 53 किलोमीटर लंबाई में मरम्मत कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष 142 किलोमीटर क्षेत्र में कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

लोक निर्माण विभाग ने बताया कि सभी मार्गों पर कार्य गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप किया जा रहा है। सड़कों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और मरम्मत कार्यों का लाभ लंबे समय तक जनता को मिले।

इन सुधार कार्यों के पूर्ण होने से सरगुजा सहित आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क और परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इससे आम नागरिकों को सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध यात्रा सुविधा प्राप्त होगी तथा क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

देशव्यापी कार्यक्रमों का शुभारंभ

धमतरी । वंदे मातरम्के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभर में जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरणादायी उद्बोधन के साथ हुआ। प्रातः 10 बजे दूरदर्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संबोधन देशभर के शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं जनप्रतिनिधि संस्थाओं में प्रत्यक्ष प्रसारित किया गया। उद्बोधन उपरांत उपस्थितजन एवं विद्यार्थियों द्वारा एक साथ वंदे मातरम्का सामूहिक गायन किया गया, जिससे देशभक्ति और एकता का संदेश गूंज उठा।

जिला स्तरीय कार्यक्रम धमतरी जिले के विकासखंड कुरूद स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सम्बलपुर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, जनप्रतिनिधि शशि पवार, उपाध्यक्ष जिला पंचायत गोकरण साहू, सभापति जिला पंचायत मोनिका देवांगन, जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल, विद्यालय प्राचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा वंदे मातरम् थीम पर बनाई गई आकर्षक चित्रकला और रंगोली प्रदर्शनी का अतिथियों ने अवलोकन किया तथा उनकी रचनात्मकता की सराहना की। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को वंदे मातरम्गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसके रचयिता महान साहित्यकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के योगदान से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम्केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत माता के प्रति समर्पण, साहस और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

उन्होंने विद्यार्थियों को अपने इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली अध्यायों से प्रेरणा लेने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि धमतरी जिले ने स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान दिया है।

वन मंत्री श्री कश्यप ने 'अबूझमाड़ पीस हाफमैराथन' के 5 वें संस्करण का पोस्टर किया विमोचन

वन मंत्री श्री कश्यप ने 'अबूझमाड़ पीस हाफमैराथन' के 5 वें संस्करण का पोस्टर किया विमोचन

मैराथन का आयोजन 25 जनवरी 2026 को

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने नारायणपुर जिले के ग्राम पंचायत खोड़गांव में आयोजित कार्यक्रम में अबूझमाड़ पीस हाफमैराथन के 5 वें संस्करण के पोस्टर का विमोचन किया। यह मैराथन अबूझमाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, झरनों, झीलों, स्थानीय जनजातीय जीवन शैली और समृद्ध लोक संस्कृति को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम होगा। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन 25 जनवरी 2026 को किया जाएगा, इसमें 21 किलोमीटर की मुख्य दौड़ आयोजित होगी, जिसके विजेताओं को लाखों रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि अबूझमाड़ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर अनमोल है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेने और इसे उत्सव सम्पन्न कराने की अपील की, ताकि मैराथन को ऐतिहासिक और सफ्ल स्वरूप दिया जा सके।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्री इन्द्रप्रसाद बघेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह मंडावी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पिंकी उसेंडी, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका के पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

बस्तर संभाग सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में विधायक विक्रम मंडावी से मांगा समर्थन

बीजापुर । शुक्रवार को बस्तर संभाग के सहकारी समिति कर्मचारी संघ बस्तर संभाग ने अपनी जायज 04 सूत्रीय मांगों को लेकर बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी से मिले और अपनी चार सूत्रीय मांगों के समर्थन में समर्थन मांगा साथ ही चार सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन विधायक विक्रम मंडावी को सौंपा है। इसके साथ ही विधायक विक्रम मंडावी ने बस्तर संभाग के सहकारी समिति कर्मचारी संघ बस्तर संभाग के अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की मांगों को जायज करार देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपने कार्यक्षेत्र में विषम परिस्थितियों में काम करते है और शासन की योजनाओं को गांवो के किसानों तक प्रदेश के 2058 सहकारी समिति के माध्यम से पंहुचाते है। इसलिए बस्तर संभाग के सहकारी समिति कर्मचारी संघ की मांग जायज है और बस्तर संभाग के सहकारी समिति कर्मचारी संघ बस्तर संभाग जगदलपुर के 04 सूत्रीय मांगों को पूरा करने हेतु संघ को पूरा समर्थन है और साथ ही सरकार से मांग है कि बस्तर संभाग के सहकारी समिति कर्मचारी संघ की 04 सूत्रीय मांगों को सरकार को जल्द पूरा करना चाहिए। विदित हो कि बस्तर संभाग के सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से 1- समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में धान परिदान पश्चात हुई संपूर्ण सुखत मान्य कर राशि समितियों को देते हुए धान खरीदी वर्ष 2024-25 कंडिका 1.10 में परिवहन पश्चात संपूर्ण सुखत समिति को दे अथवा प्रत्येक सप्ताह संपूर्ण परिवहन हो और वर्ष 2024-25 में शुन्य शार्टेज प्रोत्साहन का भी प्रावधान कर विभिन्न प्रदत्त कमीशन, प्रशांगिक।

भाठागांव में प्रीमियम अंग्रेजी शराब दुकान के विराध में उतरे लोग

पार्षद ने चेतावनी दी कि अगर जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया

रायपुर। राजधानी रायपुर के भाठागांव इलाके में शुक्रवार को नव-निर्मित प्रीमियम अंग्रेजी शराब दुकान के उद्घाटन का विरोध करने के लिए स्थानीय पार्षद अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। पार्षद ने आबकारी विभाग चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने नई शराब दुकान शुरू की, तो वे आंदोलन करेंगे और दुकान खुलने नहीं देंगे।

मिली जानकारी के अनुसार, भाठागांव क्षेत्र के नगर माता बिन्नी बाई स्कूल के समीप आबकारी विभाग द्वारा एक प्रीमियम अंग्रेजी शराब दुकान खोलने जा रही है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस निर्णय का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। वहीं शुक्रवार को पार्षद तथा स्थानीय लोग वहां शराब दुकान को विरोध करने पहुंच गये। इस दौरान लोगों ने कहा कि यहां पहले से ही देशी दारू की दुकान है, जिससे हर दिन स्कूल जाने वाले बच्चों और महिलाओं को परेशानी होती है। अब और नई दुकान खोलने से यहां का माहौल खराब होगा। जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में गहरा आक्रोश है। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, महिलाएं और युवाओं ने भी पार्षद का समर्थन किया। सभी ने एक सुर में कहा कि भाठागांव एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां स्कूल, मंदिर और बाजार मौजूद हैं। ऐसे में शराब दुकान खोलना सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने वाला कदम है। प्रदर्शन के दौरान पार्षद और नागरिकों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से तत्काल दुकान खोलने की प्रक्रिया को रोकने की मांग की। पार्षद ने चेतावनी दी कि अगर जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा, हम शराब दुकान के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो जनांदोलन छेड़ेंगे।

भारतीय वायुसेना की आकाशीय शौर्यगाथा पर डाक विभाग का नमन छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने जारी किया विशेष स्मृति फ्लोन कवर

रायपुर। नया रायपुर के शांत सेंध लेक के आकाश में भारतीय वायुसेना के 'सूर्यकिरण' विमानों की गर्जना ने साहस, अनुशासन और तकनीकी दक्षता की अद्भुत झलक प्रस्तुत की। इसी गौरवपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने एक विशेष स्मृति फ्लोन कवर , विशेष निरस्तीकरण अतिरिक्त लाल निरस्तीकरण तथा चित्र पोस्टकार्ड जारी किया। इस स्मृति डाक वस्तु को उड़ान भरने से पूर्व छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के निदेशक, डाक सेवाएँ द्वारा भारतीय वायुसेना के पायलट को सौंपा गया। तत्पश्चात यह विशेष कवर सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के विमानों द्वारा आकाश में उड़ान भरते हुए प्रतीकात्मक रूप से 'कैरिड' किया गया। यह केवल एक डाक वस्तु नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के गौरवशाली पराक्रम और भारतीय डाक विभाग की राष्ट्रसेवा भावना का संयुक्त प्रतीक है। यह स्मृति कवर गति, समरूपता, देशभक्ति और सेवा के उस अद्भुत संगम का प्रतिनिधित्व करता है जो देश की सीमाओं से लेकर जनसंचार के प्रत्येक आयाम में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल ने भारतीय वायुसेना के प्रति श्रद्धा, गौरव और राष्ट्रीय एकता के संदेश को नए आयाम प्रदान किए हैं।

नि:शुल्क हृदय जांच, 57 बच्चों की हुई स्क्रीनिंग

रायपुर, 07 नवम्बर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज शासकीय प्राइमरी स्कूल खपरी आरंग में 42 बच्चों की स्क्रीनिंग किया गया जिसमें छात्र 19 एवं छात्राएं 23 छात्राएं शामिल थीं एवं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 02 खपरी आरंग में कुल स्क्रीनिंग 15 बच्चों का किया गया जिसमें छात्र 08 एवं छात्राएं 07 शामिल थीं और कोई भी बच्चा सस्पेक्टेड नहीं मिला। शिविर के दौरान बच्चों की जांच तेज धड़कन, वजन न बढ़ना, शरीर में नीलापन, बार-बार सर्दी-खांसी, सांस लेने में तकलीफ तथा स्तनपान के समय पसीना आने जैसे लक्षणों के आधार पर की गई।

सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर स्वास्थ्य सवे

रायपुर,। सुकमा कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियद नेल्लानार योजना के तहत माओवाद प्रभावित कोंटा विकासखंड के 125 गांवों में घर-घर स्वास्थ्य सर्वे अभियान चलाया गया। दुर्गम और पहुंचविहीन क्षेत्रों में संचालित इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सीएमएचओ डॉ. आर.के. गुप्ता ने बताया कि सर्वे के दौरान संपूर्ण नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया। बीएमओ कोंटा ने जानकारी दी कि सर्वे में 624 मोतियाबिंद मरीजों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें 132 एक आंख में और 492 दोनों आंखों में मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। इन सभी मरीजों के लिए जिला अस्पताल में शीघ्र ही विशेष निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर आयोजित किए जाएंगे। मरीजों के लाने-ले जाने, भोजन एवं आवास की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

कृषि महाविद्यालय, रायपुर में किया गया वंदे मातरम के 150वें वर्ष समारोह का सीधा प्रसारण

रायपुर। मां भारती को समर्पित राष्ट्रगीत ÷वन्देमातरम÷ की 150वीं वर्षगाठ के शुभ अवसर पर आज कृषि महाविद्यालय रायपुर में राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के सीधे प्रसारण के साथ हुआ। कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सेमिनार हॉल में आयोजित इस प्रसारण कार्यक्रम में डॉ. आरती गुहे, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, रायपुर, डॉ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. के 200 से अधिक छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत से हुआ, जिसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर संचालक, अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक एवं विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री जी के विचारों को आत्मसात करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराया। महाविद्यालय परिसर में देशभक्ति एवं सांस्कृतिक एकता का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के उपरांत महाविद्यालय के अधिष्ठाता, प्राध्यापक, वैज्ञानिक एवं छात्र-छात्राओं ने उत्साह पूर्वक ÷वंदे मातरम÷ का गायन किया। अंत में डॉ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने सभी को इस ऐतिहासिक अवसर पर बधाई देते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी हेतु प्रेरित

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत कार्यशाला सम्पन्न

धमतरी । बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत जिला धमतरी को बाल विवाह मुक्त करने आज कम्पोजिट बिल्डिग में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला-धमतरी के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाईजर बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, आगनबाडी कार्यकर्ता, चाइल्ड हेल्प लाईन सहित गैर शासकीय संस्था, नशा मुक्ति केन्द्र, बालगृह, एक्जेक्ट फांउडेशन के प्रतिनिधि, किराया भंडार, कैटर्स, पुरोहित उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारभ डीएसपी एस. करण दीप ध्रुव (मुख्य अतिथि) एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जगरानी एक्का, की अध्यक्षता एवं विशेष अतिथि टुमन डडसेना, टी आई थाना केरेगाव तथा परियोजना अधिकारी सुमित गंडेचा, सरिता कुशवाहा, उषाकिरण चन्द्राकर, सोमेन्द्र साहू के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। इसके बाद वन्देमातरम गीत भी गाया गया।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुये कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह करने वाले पुरुष सहित बाल विवाह को प्रोत्साहन देने वाले व अनुष्ठान करने वाले पुरोहित एवं बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले भी अपराधी के श्रेणी में आयेंगें, जिन्हे 02 साल की सजा एवं 01 लाख रूपये जुर्माना दिये जाने का प्रावधान है। बाल विवाह की रोकथाम में आने वाले चुनैतीयों तथा अन्य विभागों की भूमिका के सम्बंध में परियोजना अधिकारी सुमित गंडेचा ने विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा की पंडित जी, टेंटवाले, कार्ड छापने, हलवाई, ज्वेलरी, मितानिन, कोटवार इत्यादि सभी की जवाबदारी हो जाती है कि वे बाल विवाह न होने के संबंध में पंचायत के आम आदमियों तक जागरूक किया जावें।

मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल : बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान के लिए चिन्हित व्यक्तियों को मिलेगी प्रति वर्ष 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ के चिन्हित व्यक्तियों को प्रति वर्ष 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को 'मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना (अनुसूचित जनजाति) वर्ष 2025' के नाम से जाना जाएगा। योजना के संबंध में 6 नवम्बर को आदिम जाति विकास विभाग द्वारा विस्तृत अधिसूचना जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वनौषधीय चिकित्सा संबंधी कार्यों में संलग्न बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ लोगों की परंपरागत वनौषधीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने और उनके सेवा एवं योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवम्बर 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा प्रति चिन्हित व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की सम्मान सह-प्रोत्साहन निधि प्रदान करने की घोषणा की गई थी। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि 'मुख्यमंत्री बैगा, गुनिया-हड़जोड़ सम्मान योजना' का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के अंतर्गत परंपरागत रूप से वनौषधियों के ज्ञान में दक्ष बैगा, गुनिया और हड़जोड़ व्यक्तियों के पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना, उसे आगामी पीढ़ियों तक हस्तांतरित करना और उनके वनौषधीय चिकित्सकीय अनुभवों का अभिलेखीकरण कर उनकी आजीविका एवं सेवा को सुदृढ़ बनाना है। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनजाति समाजों में वनौषधीय चिकित्सा संबंधी अनुभव परिवारों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों में ऐसे बैगा, गुनिया एवं हड़जोड़ व्यक्ति जो विगत तीन वर्षों से वनौषधीय चिकित्सा सेवा कार्य में संलग्न हैं, उन्हें संरक्षित करने और सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्त्री, पुरुष एवं तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति, जो बैगा, गुनिया या हड़जोड़ के रूप में कम से कम 30 वर्षों से अपने स्थानीय क्षेत्र में सेवाएँ दे रहे हैं तथा जिनके परिवार में कम से कम दो पीढ़ियों से वनौषधीय चिकित्सा का ज्ञान स्थानांतरित हुआ है, पात्र माने जाएंगे। साथ ही, जो व्यक्ति पादप औषधि बोर्ड, आयुष विभाग, वन विभाग या लघु वनोपज संघ जैसी पंजीकृत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम स्तर पर किया जाएगा। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित नामों की अनुशंसा ग्राम स्तर पर ग्राम सचिव, सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन तथा प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाला के प्रधानपाठक द्वारा अनुमोदित की जाएगी। इस अनुशंसा के आधार पर संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास स्तर पर गठित समिति – जिसमें संबंधित जनपद अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक जनपद सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) एवं मंडल संयोजक शामिल होंगे – द्वारा अनुशंसित नामों का परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा। सत्यापित सूची आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। समिति द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त सदस्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। ग्राम सभा/ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा जनपद स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के उपरांत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास को भेजा जाएगा। प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार जिलों को आवश्यक धनराशि का आबंटन किया जाएगा। तत्पश्चात सहायता राशि का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा तथा सम्मान निधि प्राप्त व्यक्तियों की सूची संबंधित ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराएं हमारे सांस्कृतिक वैभव और प्राचीन ज्ञान का जीवंत प्रतीक हैं। बैगा, गुनिया और हड़जोड़ हमारे समाज के वे सम्मानित जन हैं, जिन्होंने सदियों से वनौषधीय चिकित्सा की लोकपरंपरा को जीवित रखा है। उनकी इस अनमोल सेवा और ज्ञान को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ सम्मान योजना प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से हम न केवल उनके योगदान को मान्यता दे रहे हैं, बल्कि उनकी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को संरक्षित करते हुए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प भी निभा रहे हैं। -

जनजातीय गौरव दिवस पर समूचे प्रदेश में 1 से 15 नवम्बर तक मनाया जाएगा जनजातीय गौरव पखवाड़ा

धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर होंगे विशेष आयोजन

रायपुर । भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार इस वर्ष 15 नवम्बर 2025 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में समूचे देश में जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 1 नवम्बर से 15 नवम्बर 2025 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि एवं प्रभारी सचिवों की उपस्थिति में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह में जनजातीय संस्कृति, लोककला, व्यंजन, हस्तशिल्प और विकास प्रदर्शनी के साथ-साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रमों में शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव एवं उत्तर छत्तीसगढ़ जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आश्रम-छात्रावासों, शासकीय संस्थानों और जनजातीय ग्रामों में प्रभातफेरी, जन-जागरूकता यात्राएँ, वृक्षारोपण, निबंध, वाद-विवाद एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी। जनजातीय नायक-नायिकाओं के जीवन और योगदान पर संगोष्ठियाँ भी होंगी। इस पखवाड़े के दौरान विशेष लाभार्थी संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, सिकल सेल जांच, स्वास्थ्य परीक्षण, जाति प्रमाणपत्र वितरण, पीएम किसान सम्मान निधि एवं किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। जिले के आदि सेवा केन्द्रों में भी गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा।

एनटीपीसी सीपत ने गौरव और नवऊर्जा के साथ मनाया एनटीपीसी लिमिटेड का 51वां स्थापना दिवस

रायपुर। एनटीपीसी सीपत में देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का 51वां स्थापना दिवस उत्साह, गर्व और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख विजय कृष्ण पाण्डेय को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने से हुई। तत्पश्चात् उन्होंने एनटीपीसी ध्वज फहराकर स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में पाण्डेय ने एनटीपीसी के गौरवशाली 50 वर्षों की यात्रा को स्मरण करते हुए सभी कर्मचारियों को 51वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी लिमिटेड आज देशभर में लगभग 108 विद्युत स्टेशनों के माध्यम से करीब 85,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ कार्य कर रही है और देश के हर चौथे बल्ब को रोशन करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। परियोजना प्रमुख ने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी 2,980 मेगावाट की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि निर्माणाधीन 800 मेगावाट की स्टेज-3 इकाई का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी सीपत न केवल विद्युत उत्पादन में बल्कि नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार के क्षेत्रों में भी सराहनीय योगदान दे रही है। स्थापना दिवस के अवसर पर एनटीपीसी सीपत द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत के लक्ष्य को साकार करने के उद्देश्य से एक विशेष पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत एक ही दिन में कुल 4,000 पौधे लगाए गए, जिनमें से 2,000 पौधे ग्राम करमा में तथा 2,000 पौधे परियोजना परिसर में रोपे गए। इसी अवसर पर 160 किलोवाट क्षमता के रूफ्टॉप सोलर पैनल का भी शुभारंभ किया गया, जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही हाल ही में मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि ने एनटीपीसी सीपत की सफलता में सहयोग दे रहे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, संगवारी महिला समिति, विभिन्न यूनियन एवं एसोसिएशन, बाल भारती पब्लिक स्कूल, संस्कृति क्लब, वैशाली क्लब, स्टेट बैंक ऑफइंडिया, डाकघर, इंडियन कॉफी हाउस तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं के समर्पित योगदान की सराहना की और सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधकगण, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी, यूनियन एवं एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से केक काटकर स्थापना दिवस का उत्सव मनाया।

देशदेखा में पर्यटक झूमे लोक कलाकारों के साथ, चांदनी रात में किया स्टार ग्रेजिंग का आनंद

जशपुर जम्बुरी में लोक संस्कृति और प्रकृति का संगम :

जशपुर जम्बुरी में लोक संस्कृति और प्रकृति का संगम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में आयोजित जशपुर जम्बुरी 2025 का पहला दिन लोक संस्कृति, आतिथ्य और प्राकृतिक सौंदर्य के रंगों से सराबोर रहा। देशदेखा पहुंचे देशभर के पर्यटक न केवल जशपुर की मनमोहक वादियों में खो गए, बल्कि लोक कलाकारों के साथ पारंपरिक नृत्य और संगीत की थाप पर झूम उठे।पहले दिन जम्बुरी में 120 पर्यटकों का पंजीयन किया गया। उनका स्वागत जशपुर की परंपरागत शैली में किया गया और स्थानीय शुद्ध दोना-पत्तल में पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। अतिथियों ने स्थानीय भोजन के स्वाद और जशपुरवासियों के आत्मीय सत्कार की प्रशंसा की।सांझ ढलते ही चांदनी रात में देशदेखा का आसमान सितारों से जगमगा उठा। पर्यटकों ने खुले आसमान के नीचे स्टार ग्रेजिंग सेशन का आनंद लिया, जो जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से आयोजित किया गया था। तारों के बीच बैठकर लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया।लोक संस्कृति की जीवंत झलकियों के बीच पर्यटकों ने नृत्य, संगीत और पारंपरिक वेशभूषा के माध्यम से जशपुर की समृद्ध विरासत को करीब से महसूस किया। इस अनुभव ने न केवल उन्हें रोमांचित किया बल्कि राज्य के इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई ऊँचाई दी।

दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़कपुर रेल मण्डल के शालीमार यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा

रायपुर । दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़कपुर रेल मण्डल के शालीमार यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा । यह कार्य दिनांक 13 से 23 नवम्बर, 2025 तक किया जा रहा है । इस कार्य के फलस्वरुप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है । 01. दिनांक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 एवं 23 नवम्बर, 2025 को एलटीटी से चलने वाली 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।02. दिनांक 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 नवम्बर, 2025 को शालीमार से चलने वाली 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी । दिनांक 12, 13 एवं 19 नवम्बर, 2025 को एलटीटी से चलने वाली 12151 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी ।

04. दिनांक 14, 15 एवं

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने किया भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्यालय भवन का भूमि पूजन

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने किया भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्यालय भवन का भूमि पूजन स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने किया भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्यालय भवन का भूमि पूजन

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव आज माध्यमिक शिक्षा मंडल, पेंशनबाड़ा कार्यालय परिसर में आयोजित भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्यालय कार्यालय भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंत्री श्री यादव ने कहा कि ÷जिस भाव से स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना की गई थी, वह भाव सदैव बना रहना चाहिए। स्काउट गाइड हमें आनंद के साथ जीना सिखाता है। राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को और अधिक सुदृढ़ एवं उत्कृष्ट

बनाया जाएगा।÷ श्री यादव ने यह भी आश्वासन दिया कि आज भूमि पूजन संपन्न हुआ है और अगले एक वर्ष के भीतर राज्य कार्यालय, भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंदरजीत सिंह खालसा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर स्काउट एवं गाइड आंदोलन के उद्देश्यों और युवा सशक्तिकरण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। अन्य विशिष्ट अतिथियों में माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू, राज्य कोषाध्यक्ष श्री मुरलीधर शर्मा तथा श्री जी. स्वामी जी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन राज्य सचिव, भारत स्काउट एंड गाइड्स श्री जितेंद्र कुमार साहू, ने दिया

युक्तियुक्तकरण नीति से विद्यार्थियों तक पहुँच रही शिक्षकों की विशेषज्ञता का लाभ

मिडिल स्कूल लैंगा में शिक्षक गोरेलाल कंवर के आने से हिंदी विषय में बढ़ी विद्यार्थियों की रुचि

रायपुर। देश सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति के तहत विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पदस्थापना से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, लैंगा में हिंदी विषय के शिक्षक श्री गोरेलाल कंवर की नियुक्ति हुई है। विद्यालय में उनके आने के बाद से हिंदी विषय विद्यार्थियों के लिए रोचक और प्रेरणादायक बन गया है।

शिक्षण शैली ने बच्चों में जगाई सीखने की जिज्ञासा

श्री कंवर की शिक्षण शैली अत्यंत रोचक, जीवंत और प्रभावशाली है। वे गद्य, पद्य, व्याकरण और साहित्य के हर पहलू को बच्चों तक सरल और रचनात्मक ढंग से पहुँचाते हैं। नाट्य

रूपांतरण, संवाद, कहानी, गीत और गतिविधि-आधारित शिक्षण के माध्यम से वे बच्चों को सीखने में सम्मिलित करते हैं। कक्षा 8 वीं के छात्रों ने बताया कि जब श्री कंवर ने इतिहास विषय में तैमूर लंग के भारत आक्रमण से संबंधित पाठ का मंचन कराया, तो इतिहास जैसे विषय जीवंत हो उठा। बच्चों की आँखों में जिज्ञासा की चमक और सीखने का उत्साह देखने लायक था। शिक्षक गोरेलाल कंवर के प्रयासों से अब हिंदी विषय विद्यार्थियों के लिए कठिन नहीं बल्कि मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बन गया है। रस, छंद, अलंकार जैसे व्याकरण के अंश अब बच्चों को सहज लगने लगे हैं। छात्र-छात्राएँ – कु. अनुसुइया, अंश, रश्मि, कल्पना, महिमा और लवकेश – ने बताया कि अब उन्हें हिंदी पढ़ना आनंददायक लगता है और वे कविता पाठ, कहानी लेखन व भाषण जैसी गतिविधियों में भी भाग लेने लगे हैं।

अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास में भी हो रहा विकास

श्री कंवर केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि बच्चों में अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। वे छात्रों को कहानी रचना, पत्र लेखन, कविता पाठ और भाषण देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है।

अभिभावकों और प्रधानपाठक ने की नीति की सराहना

विद्यालय के प्रधानपाठक एवं अभिभावकों ने राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति की सराहना करते हुए कहा कि विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यह नीति शिक्षकों की विशेषज्ञता का लाभ सही रूप में विद्यार्थियों तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रही है।

व्यापम द्वारा आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र केंद्राध्यक्ष, परिवहन अधिकारी (आब्जर्वर) की बैठक

अभ्यर्थी आधी बांह वाले हल्के रंग के कपड़े पहने, कान में किसी प्रकार का आभूषण है वर्जित

रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यापम रायपुर द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर केंद्राध्यक्ष, परिवहन अधिकारी (आब्जर्वर) की रेडक्रॉस सभाकक्ष, कलेक्ट्रट में नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर उपेंद्र किण्डो ने आज गुरुवार को बैठक ली। बैठक में सभी केंद्रों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा सभी केंद्रों में दीवाल घड़ी लगाने संबंधित निर्देश दिए ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला भर्ती परीक्षा 09 नवंबर 2025, रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 01.15 बजे तक 09 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। जिसमें 2488 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यार्थियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश :- हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाए एवं काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैंगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनना वर्जित होगा । परीक्षार्थी, परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचे ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। चूंकि यह परीक्षा प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ हो रहा है अतः मुख्य द्वार प्रातः 10.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये। धार्मिक एवं सांस्कृतिक

संपादकीय

ट्रेड वार से क्यों पीछे हटे ट्रंप

चीन-अमेरिका ट्रेड वार पर थोड़ा अंकुश लगता दिख रहा है। चीन रेयर अर्थ के निर्यात और अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर कुछ राहत दे सकता है, मगर इसके बदले उसने अमेरिका से अमेरिकी बंदरगाहों पर चीन निर्मित एवं संचालित जहाजों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी पर जोर दिया है। साथ ही उसने चीनी कंपनियों पर पिछले महीने लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने की मांग की है। ट्रंप- शी वार्ता में इन सहमतियों पर दस्तखत हो जाते हैं। ऐसा हुआ, तो अमेरिका और चीन के अलावा अन्य देशों को भी राहत मिलेगी। मगर जो ठोस हालात हैं, उनके मद्देनजर यह करार भी एक युद्धविराम ही होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली ने दो टूक कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध में बार-बार विच्छेद और उनका अल्पकालिक समाधान आज की हकीकत है। अमेरिकी विश्लेषक भी इस बात से लगभग सहमत ही हैं।

संस्मरण : प्रेमेन्द्र अग्रवाल

सिगरेट, जिसे याद करके मुझे आज भी शर्म आती है।

बेटा: लेकिन एक और बात है जिसे याद करके मुझे आज भी शर्म आती है।

माँ: (मुस्कुराते हुए) ओह? अब क्या है?

बेटा: जब भी अंकल नारनौल से आते थे, तो वे उसी बरामदे में बैठते थे, सिगरेट पीते थे, और जाने से पहले सिगरेट के टुकड़े ज़मीन पर फेंक देते थे। मैं तब बस एक जिज्ञासु बच्चा था... और उनके जाने के बाद, मैं चुपके से उन टुकड़ों को उठाता था और उन्हें अपने होठों के बीच रखता था - उनके जैसा सिगरेट पीने का नाटक करता था।

माँ: (धीरे से हँसती है) अरे प्यारे, बच्चे यही करते हैं - बिना सोचे-समझे बड़ों की नकल करते हैं।

बेटा: मुझे पता है... लेकिन आज भी, जब भी मुझे वह याद आता है, तो मुझे शर्म आती है।

माँ: शर्म मत करो। ये छोटी-छोटी बेवकूफी भरी बातें ही हमारे बचपन को इतना इंसानी और यादगार बनाती हैं।

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा
लिखित पुस्तकें पढ़िये
ऑनलाईन

PM : 2024 - Vishwa Sarkar Ka Vikalp

Modimaya_ Vaidik_Netritva

Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-Bhrasht Tantra

Silent Assassins Jan11,1966

Accursed & Jihadi Neighbour

एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, महंगाई-बेरोजगारी पर विपक्ष रहेगा हमलावर

अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार

एक दिसंबर 2025 से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और सियासी वातावरण धीरे-धीरे तपने लगा है। यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र की नीतियों को लेकर विपक्ष पहले से ही हमलावर मूड में है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार बनाम विपक्ष का आमना-सामना कई प्रमुख मुद्दों पर देखने को मिल सकता है। बीते महीनों में हुए कुछ निर्णयों, आर्थिक नीतियों, किसानों की मांगों और राज्यों में घटित राजनीतिक घटनाओं ने संसद में तीखी बहस के संकेत दे दिए हैं। सत्र का एजेंडा भले ही सरकार तय करती है, पर माहौल विपक्ष के आक्रामक तेवरों से ही बनता है। बिहार चुनाव के नतीजे और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा एसआईआर का विरोध भी सत्र को प्रभावित कर सकते हैं।विपक्ष के निशाने पर सबसे पहला और बड़ा मुद्दा महंगाई का रहेगा। त्योहारी सीजन के बाद खाद्य पदार्थों की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। दाल, तेल, सब्जियों और दूध के दामों ने आम जनता की जेब पर असर डाला है। विपक्ष इसे जनता के जीवन से जुड़ा विषय बनाकर पेश करेगा और सरकार से सवाल करेगा कि महंगाई पर नियंत्रण के इतने वादों के बावजूद कीमतें क्यों नहीं थम रही हैं। खासकर रसोई गैस और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें विपक्ष को सरकार को घेरने का खुला मौका देंगी। दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नई नौकरियों की घोषणा के बावजूद युवाओं में बेचैनी कम नहीं हुई है। विपक्ष यह साबित करने की कोशिश करेगा कि रोजगार सृजन के सरकारी दावे केवल आंकड़ों तक सीमित हैं। इस विषय पर विपक्ष का फोकस युवाओं को साधने पर रहेगा, खासकर उन राज्यों में जहां आने वाले महीनों में चुनाव होने हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियां इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी में हैं। विपक्ष चाहता है कि संसद के अंदर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं की चर्चा इतनी तीखी हो कि बाहर जनता में उसकी गूंज बने।

कृषि और किसानों से जुड़ा मामला भी सत्र में खूब गूंज सकता है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर से किसान संगठनों का दबाव बढ़ रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, फसलों के दामों की स्थिरता और कृषि कानूनों से जुड़े पुराने विवाद विपक्ष के हथियार बन सकते हैं। भले ही सरकार ने कुछ नीतिगत घोषणाएं की हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठाएगा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। राष्ट्रव्यापी किसान संगठनों की योजनाबद्ध रणनीति संसद सत्र के दौरान सड़क से सदन तक समानांतर आंदोलन का रूप ले सकती है।सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दे भी विपक्ष के निशाने पर रहने वाले हैं। बीते महीनों में जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और लद्दाख क्षेत्र में घटनाओं ने सरकार की आंतरिक सुरक्षा नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष इस प्रश्न को उठाएगा कि शांति और विकास के वादों के बावजूद इन संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थिरता क्यों बनी हुई है। इसके अलावा, सीमा विवाद और रक्षा सौदों की पारदर्शिता जैसे विषयों पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। रक्षा बजट और आधुनिक तकनीक की उपलब्धता पर विस्तृत चर्चा की मांग विपक्ष के एजेंडे में शामिल है।

शीतकालीन सत्र का एक और संभावित विवादास्पद मुद्दा जनगणना और जाति आधारित सर्वेक्षण से जुड़ा हो सकता है। कई राज्यों ने जातीय सर्वेक्षणों के आंकड़े जारी किए हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति को लेकर बहस तेज हुई है। बिहार, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में हुए सर्वेक्षणों ने सामाजिक समीकरण की नई परतें खोली हैं। विपक्ष केंद्र से यह सवाल करेगा कि अगर राज्य स्तर पर जाति आधारित सर्वेक्षण संभव हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर केंद्र अब तक चुप क्यों है। यह मुद्दा सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा दे सकता है और संसद में लंबी बहस को जन्म दे सकता है।मणिपुर हिंसा और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मानवाधिकार के सवाल भी विपक्षी एजेंडे में शामिल रहेंगे। विपक्ष सरकार से यह पूछने की कोशिश करेगा कि क्या इन मामलों में प्रशासन की निष्पक्षता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई है या नहीं। मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को विपक्ष बहस में शामिल कर सकता है, जिससे सरकार पर नैतिक दबाव बने।अर्थव्यवस्था से जुड़ी नीतियों पर जैसे जीएसटी संग्रह, औद्योगिक विकास और छोटे व्यापारियों की कठिनाइयों पर भी विपक्ष का हमला होगा। विपक्ष यह तर्क देगा कि विकास का लाभ केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों तक सीमित है, जबकि छोटे व्यवसाय दबाव में हैं। वित्तीय घाटा और रुपये की गिरावट को लेकर भी प्रश्न उठ सकते हैं। खासकर पेट्रोल और डीजल पर कर, विदेशी निवेश और पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट की नीतियों को विपक्ष जमकर मुद्दा बनाएगा।

मीडिया स्वतंत्रता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जैसे सवाल भी इस बार गूंज सकते हैं। विपक्ष यह आरोप लगा सकता है कि संवैधानिक संस्थाएँ केंद्र के प्रभाव में काम कर रही हैं। इससे लोकतंत्र की सेहत पर बहस छिड़ सकती है। सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) में संशोधन और मीडिया नियमन से जुड़ी हालिया चर्चाएं भी इस बहस का हिस्सा बनेंगी। जनहित के कानूनों और सामाजिक योजनाओं पर बहस में विपक्ष यह दिखाने की कोशिश करेगा कि सरकारी घोषणाओं और जमीनी हकीकत में फर्क है। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना जैसी योजनाएँ हर सत्र में चर्चा का विषय रहती हैं और इस बार भी विपक्ष इनके कार्यान्वयन पर सवाल उठाएगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं की पहुंच और गुणवत्ता को लेकर विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करने की कोशिश करेगा। इन सारे मुद्दों के बीच विपक्ष की एक और रणनीति होगी कि सरकार को जवाब देने पर मजबूर किया जाए। प्रश्नकाल और शून्यकाल का अधिकतम उपयोग इसी दिशा में होगा। हालांकि सरकार भी इस सत्र को अपने विधायी एजेंडे के हिसाब से आगे बढ़ाना चाहेगी, जिसमें आर्थिक सुधारों से जुड़े कुछ नए विधेयक शामिल हो सकते हैं। लेकिन संसद का वास्तविक माहौल विपक्ष के शोर-शराबे और सदन के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष की राजनीतिक अदाओं से ही तय होगा।इस सत्र का राजनीतिक महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगले वर्ष कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह सत्र केवल नीति निर्माण का नहीं, बल्कि आगामी चुनावी नैरेटिव तय करने का अखाड़ा भी बन जाएगा। विपक्ष जहां जनता के सवालों को मुखर करना चाहता है, वहीं सरकार अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश कर जनता को भरोसे में लेने की कोशिश करेगा।

यह निजी विचार है।

भारत के श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में : श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की आवश्यकता

एस.पी. तिवारी

भारत का कार्य जगत एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। देश की श्रमशक्ति को लिखित अनुबंधों, पर्याप्त मजदूरी और व्यापक सामाजिक सुरक्षा द्वारा समर्थित औपचारिक रोजगार में तेजी से जगह मिलनी चाहिए ताकि विकास के लाभ सभी के लिए सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण आजीविका में बदल सकें। पुराने विनियामक ढांचों के बने रहने के चलते, आंशिक रूप से, औपचारिकीकरण की गति और उद्यमों की सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण नौकरियां सृजित करने की क्षमता सीमित हो गई है। वर्ष 2019 और 2020 के बीच संसद द्वारा मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज की स्थितियों के संबंध में पारित चार श्रम संहिताएं 2002 में रवींद्र वर्मा की अध्यक्षता वाली द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा परिकल्पित लंबे समय से लंबित सुधारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस श्रम आयोग का मिशन तत्कालीन मौजूदा श्रम ढांचे को संहिताबद्ध, सरल और संशोधित करना था। ये नई संहिताएं देश के श्रम परिदृश्य को आधुनिक बनाने और संरचनात्मक असंतुलनों को दूर करने हेतु एक व्यापक ढांचा प्रदान करती हैं। सभी राज्यों में इनका एकसमान कार्यान्वयन अब एक बेहद जरूरी राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है।

ये नई संहिताएं 29 केन्द्रीय श्रम कानूनों को सरल और आधुनिक बनाती हैं। इन कानूनों में से कई बीसवीं सदी के मध्य के हैं। इन संहिताओं का उद्देश्य न केवल कानूनों का विलय करना है, बल्कि श्रमिकों/कर्मचारियों की विभिन्न परिभाषाओं को एक सरल परिभाषा में बदलना भी है। प्रत्येक संहिता श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण को सुदृढ़ करती है और साथ ही नियोक्ताओं के लिए स्पष्टता और पूर्वानुमेयता प्रदान करती है।

उचित मजदूरी और श्रम की गरिमा

वेतन संहिता, 2019 प्रत्येक श्रमिक को श्रम की गरिमा का सम्मान करने वाला वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करके, यह संहिता इस बात की गारंटी देती है कि कोई भी श्रमिक, चाहे वह किसी भी पेशे या स्थान से जुड़ा हो, एक बुनियादी मानक आय से वंचित नहीं रहेगा। उद्योग की अनुसूची को समाप्त करने से सार्वभौमिक वेतन का मार्ग प्रशस्त होता है।

समय पर भुगतान के प्रावधानों को मजबूत किया गया है। इससे देरी की वह समस्या दूर हुई है, जो पहले परिवारों को कर्ज में धकेल देती थी। अब कर्मचारी अप्रदत्त वेतन या बोनस का दावा आसानी से कर सकते हैं और ऐसे विवादों में सबूत पेश करने का भार नियोक्ता पर होता है, जिससे जवाबदेही बढ़ती है।

साथ ही, यह संहिता उद्यमों के लिए अनुपालनों को सुव्यवस्थित करती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड-कीपिंग, एकल पंजीकरण एवं एकीकृत रिटर्न कागजी कार्रवाई को कम करते हैं और हेरफेर की आशंकाओं को घटाते हैं।

सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 आजाद भारत में कल्याण के सबसे समावेशी विस्तारों में से एक है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम सहित नौ प्रमुख कानूनों को एकीकृत करके, यह संहिता एक ऐसी एकीकृत प्रणाली स्थापित करती है जो पारंपरिक और भविष्य के कार्य, दोनों को कवर करती है।

यह पहली बार है जब गिग श्रमिकों, प्लेटफॉर्म श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के लोगों को स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय श्रमशक्ति का हिस्सा माना गया है। प्रत्येक श्रमिक को ई-श्रम पोर्टल के जरिए पंजीकृत किया जाएगा और एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा संख्या प्रदान की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और मातृत्व सहायता जैसे लाभों का सीधा वितरण संभव हो सकेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय व राज्य सामाजिक सुरक्षा कोष बनाए जायेंगे कि ऐप-आधारित डिलीवरी पार्टनर या निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूर जैसे श्रमिक भी अब सुरक्षा के दायरे से बाहर न रहें और निधियों का समग्र प्रबंधन संभव हो।

इस संहिता में करियर केन्द्र, डिजिटल एवं भौतिक प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं जो व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श और रोजगार सेवाएं प्रदान करेंगे। यह संस्थागत समर्थन कल्याण को बहु-रोजगार क्षमता से जोड़ेगा, जिससे श्रमिकों को असुरक्षा की स्थिति से निकलकर अवसर की दिशा में बढ़ने में मदद मिल सकेगी।

कार्यस्थल पर सुरक्षा, गरिमा और समानता

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (ओएसएच संहिता), राष्ट्र निर्माण करने वालों की देखभाल और उनके प्रति जिम्मेदारी का एक संदेश है। ÷प्रतिष्ठान÷ की परिभाषा को व्यापक बनाकर, यह संहिता उन लाखों लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है जो पहले सुरक्षा कानूनों के दायरे में नहीं आते थे।

यह श्रमिकों के निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य करती है और नियोक्ताओं से कर्मचारियों पर कोई वित्तीय बोझ डाले बिना सुरक्षित एवं स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखने की अपेक्षा करती है। राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन बदलती औद्योगिक परिस्थितियों के अनुरूप सुरक्षा मानकों का विकास सुनिश्चित करता है।

ओएसएच संहिता लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित करती है। महिला श्रमिकों को सभी प्रतिष्ठानों और रात्रि पाली में काम करने की अनुमति है, बशर्ते पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध हों। इससे अधिक संख्या में महिलाओं को श्रम बल में शामिल होने व बने रहने का अधिकार मिलता है। प्रवासी श्रमिकों को भी एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्रणाली के जरिए मान्यता हासिल होती है। इससे कल्याणकारी योजनाओं और आवागमन संबंधी लाभों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होती है और बेहतर जीवन एवं आजीविका सुनिश्चित करने हेतु कानूनी ढांचे की निगरानी संभव होती है।

कैंटीन और शौचालय जैसी सुविधाएं अब निचले पायदान तक अनिवार्य हैं और ऐसे प्रावधानों के निर्धारण के क्रम में ठेका श्रमिकों को भी शामिल किया जाता है। ये उपाय न्यूनतम अनुपालन से हटकर श्रमिकों के कल्याण के प्रति वास्तविक चिंता की दिशा में होने वाले बदलाव को दर्शाते हैं।

संवाद और औद्योगिक सद्भाव

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच संबंधों में स्पष्टता लाती है और एक एकीकृत ढांचे के साथ तीन पुराने अधिनियमों की जगह लेती है। इसके तहत बीस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिकायत निवारण समितियां स्थापित करना अनिवार्य है ताकि विवादों के हड़ताल या मुकदमेबाजी में बदल जाने से पहले ही उनका शीघ्र समाधान उद्यम स्तर पर सुनिश्चित हो जाए।

ट्रेड यूनियनों को एक समझौतावादी संघ या परिषद की अवधारणा के जरिए मान्यता हासिल होती है, जिससे सामूहिक सौदेबाजी को बल मिलता है और श्रमिकों को अपने कार्यस्थल को आकार देने में एक प्रभावी भागीदारी हासिल होती है। छंटनी का सामना कर रहे श्रमिक अब 30 दिन का नोटिस और पर्याप्त मुआवजा पाने के हकदार हैं। यह एक मानवीय सुधार है, जो आजीविका की सुरक्षा का सम्मान करता है। छंटनीग्रस्त श्रमिकों के लिए एक पुनः कौशल निधि (रिस्किलिंग फंड) की स्थापना एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का संकेत देती है, जो बदलती अर्थव्यवस्था में सीखने और अनुकूलनशीलता को महत्व देती है। हड़ताल के अधिकार से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बंदी या तालाबंदी की आसान मंजूरी के लिए उद्योगों के लिए श्रमिकों की सीमा को बढ़ाकर 300 तक करने के प्रावधान पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

इस संहिता द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त निश्चित अवधि का रोजगार, उद्योग जगत को लचीलापन प्रदान करता है और साथ ही नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और ग्रेच्युटी सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में समानता की गारंटी देता है। यह कदम आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों और उसमें काम करने वालों के औचित्य एवं सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करता है।

कार्यान्वयन अब क्यों जरूरी

विभिन्न विकासशील देशों से मिले साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि श्रम सुधारों ने आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बढ़ते टैरिफ और व्यापार के बदलते पैटर्न से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों की पृष्ठभूमि में, भारत को अपने नए श्रम कानूनों को तत्काल लागू करना जरूरी है। सरल एवं पारदर्शी कानून निवेश को आकर्षित करेंगे, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देंगे और श्रमिकों की गरिमा को बनाए रखेंगे। समय पर अधिसूचना भारत को विकसित देशों का दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

एक ऐसे दौर में जब स्वचालन और डिजिटलीकरण पारंपरिक नौकरियों के खत्म हो जाने का खतरा पैदा कर रहे हैं, ये संहिताएं संतुलित विकास का एक ऐसा ढांचा प्रदान करती हैं जो तकनीकी प्रगति के बावजूद मानवीय गरिमा को बनाए रखता है। सभी राज्यों में इनके कार्यान्वयन से एक समान मानक बनेंगे, अस्पष्टता कम होगी और नौकरियां आसानी से सुलभ होंगी।

आगे की राह – ये चार संहिताएं एक ऐसे आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की महत्वाकांक्षा की रीढ़ हैं, जो आर्थिक गतिशीलता और सामाजिक न्याय के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। ये संहिताएं निरीक्षकों को सुविधाप्रदाता में बदल देती हैं, पुराने एवं परस्पर विरोधी कानूनों को स्पष्ट व सुसंगत कानूनों से बदल देती हैं और श्रमिकों के कल्याण को आर्थिक नीति के केन्द्र में रखती हैं।

कुछ शर्तों के साथ इन सुधारों की भावना केवल एकीकरण में ही नहीं, बल्कि करुणा में भी निहित है। ये सुधार यह सुनिश्चित करते हैं कि कारखाने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, हर कर्मचारी को सम्मान, सुरक्षा और संरक्षा मिले। श्रमिकों के लिए, ये सुधार निष्पक्षता और अवसर का वादा करते हैं। इसलिए, इन संहिताओं को शीघ्रता और एकरूपता के साथ लागू करना न केवल प्रशासनिक तात्कालिकता, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का भी विषय है ताकि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सके जहां विकास सबका साझा हो, काम का सम्मान हो और भारत की प्रगति में योगदान देने वाले हर हाथ की रक्षा हो एवं उनके जीवनयापन में आसानी हो।

(राष्ट्रीय महासचिव, ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी)

विज्ञान में करुणा का समावेश ही विश्वशांति का सूत्र

लेखक : प्रो. (डॉ.) मनमोहन प्रकाश

हर वर्ष 10 नवम्बर को विश्वभर में ÷शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस÷ मनाया जाता है। यह दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों के उत्सव का दिन नहीं, बल्कि उस आत्ममंथन का क्षण भी है जब विश्व के विभिन्न देशों के शासक और राजनेता यह विचार करे कि क्या विज्ञान का प्रयोग वास्तव में मानव कल्याण, प्रकृति-संतुलन और विश्वशांति के लिए हो रहा है? विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी तटस्थता में निहित है।वह न तो स्वभावतः शुभ है, न अशुभ। उसकी दिशा मनुष्य की नीयत और मूल्यनिष्ठा निश्चित करती है। जब विज्ञान में करुणा और नैतिकता का समावेश होता है, तब वही ज्ञान विश्वशांति का सूत्र बन जाता है।आज विज्ञान ने मानव जीवन को जितनी सुविधाएँ और संभावनाएँ दी हैं, उतने ही गंभीर प्रश्न भी उपस्थित किए हैं। चिकित्सा, सूचना, अंतरिक्ष, ऊर्जा और संचार आदि के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, पर उसी विज्ञान के दुरुपयोग ने परमाणु हथियार, जैविक युद्ध, साइबर अपराध और पर्यावरणीय विनाश जैसी भयावह स्थितियाँ उत्पन्न की हैं। यह विरोधाभास बताता है कि विज्ञान का मूल्य उसकी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उसके प्रयोग की भावना में निहित है। जब विज्ञान करुणा और विवेक से संचालित होता है, तब वह सृजन का पर्याय बनता है; किंतु जब उसमें लोभ, सत्ता और अहंकार प्रवेश कर जाते हैं, तो वही विज्ञान विनाश का साधन बन जाता है।

21वीं सदी के इस तकनीकी युग में विज्ञान की उपलब्धियाँ अभूतपूर्व हैं, पर उसी अनुपात में उसका दुरुपयोग भी बढ़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीन-संपादन, निगरानी तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग जहां जीवन को आसान बना रहा है, वहीं इनका अनियंत्रित और अनैतिक प्रयोग मानव गोपनीयता, स्वतंत्रता और अस्तित्व पर प्रत्यक्ष संकट बनकर उभरा है। डीपफेक, डिजिटल हथियारकरण, सूचना-प्रवंचना और साइबर युद्ध जैसे आयामों ने विज्ञान को भय का प्रतीक बना दिया है। पर्यावरण में बढ़ता कार्बन, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, और स्वास्थ्य के नाम पर रचित कृत्रिम विषाक्तता इस बात की चेतावनी देते हैं कि यदि विज्ञान से संवेदना और जिम्मेदारी का तत्व विलुप्त हो गया, तो उसकी प्रगति स्वयं मानवता के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न बन जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि विज्ञान का हर नवाचार जीवन के प्रति आदर और नैतिक सीमाओं के भीतर रहे।विज्ञान का जन्म जिज्ञासा से हुआ, पर इसका चरम उद्देश्य करुणा और कल्याण होना चाहिए। जब विज्ञान ने मानव सेवा का रूप लिया, तब उसने रोगों को हराया, अंधकार को प्रकाश में बदला, और जीवन को दीर्घ, सुरक्षित और सहज बनाया। पर जब यही विज्ञान स्वार्थ, सत्ता और प्रभुत्व की राजनीति के अधीन हुआ, तब उसने युद्ध, भय और अविश्वास को जन्म दिया। परिषदों, नवाचार मंचों और प्रयोगशालाओं में अब समय है कि तकनीक की दिशा को नैतिक बुद्धिमत्ता से जोड़ा जाए।विकास का अर्थ केवल तकनीकी वृद्धि या औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नहीं, बल्कि उस प्रगति का मानवीय लाभ है। विज्ञान तभी सार्थक है जब उसकी उपलब्धियाँ सबके लिए सुलभ हों। चिकित्सा, कृषि, ऊर्जा और डिजिटल नवाचार तब ही अपने उद्देश्य तक पहुँचते हैं जब वे पीड़ित मानव तक राहत और सशक्तिकरण का साधन बनें। हरित ऊर्जा तभी अर्थपूर्ण है जब वह पृथ्वी के संतुलन और पर्यावरण की रक्षा करे। जब विज्ञान में संवेदना और उत्तरदायित्व का संगम होता है, तब विकास स्थायी बनता है और समाज में शांति का वातावरण निर्मित होता है।

युनेस्को द्वारा वर्ष 2001 में आरंभ किया गया विश्व विज्ञान दिवस इस विश्वास का प्रतीक है कि विज्ञान सीमाएँ नहीं, बल्कि सेतु बनाता है। जब विश्व के वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, महामारी या ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों के समाधान हेतु एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब वे मानवता के साझा भविष्य की रक्षा करते हैं। यही सहयोग और सहानुभूति विश्वशांति की वास्तविक नींव है। सच्चा वैज्ञानिक वही है जो अपने अनुसंधान में मनुष्य की करुणा और पृथ्वी की पुकार को एक साथ सुन सके।

भारत की वैज्ञानिक ज्ञान परंपरा सदैव ÷वसुधैव कुटुम्बकम्÷ की भावना से प्रेरित रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और दर्शन ने विज्ञान को लोककल्याण, पर्यावरण-संरक्षण और मानव सेवा का माध्यम माना है। आज भारत हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल नवाचार तथा चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में न केवल नवाचार कर रहा है, बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि विज्ञान तभी महान है जब उसमें करुणा, नैतिकता और वैश्विक हित की भावना जीवित रहे।विज्ञान शक्ति प्रदान करता है, पर दिशा नहीं। दिशा देती है करुणा। यदि विज्ञान का मार्ग करुणा और संवेदना से आलोकित हो, तो वह मानवता का रक्षक और विश्वशांति का सबसे प्रबल सूत्र बन सकता है।

सहकारिता और समुदाय-आधारित मॉडलों का सशक्तिकरण

नईदिल्ली,एजेंसी

भारत सरकार ने एक समृद्ध और समावेशी समुद्री अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 04.11.2025 को ÷विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य पालन के टिकाऊ उपयोग÷ के नियमों को अधिसूचित किया है। भारत के समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता से प्रेरित यह पहल, बजट 2025-26 की उस घोषणा को पूरा करती है जिसमें अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय ईईजेड और विशाल सागरों से टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए एक सक्षम ढाँचे की परिकल्पना की गई थी।

सहकारिता और समुदाय-आधारित मॉडलों का सशक्तिकरण - ये नियम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यों को करने और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों के प्रबंधन के लिए मछुआरा सहकारी समितियों और मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को प्राथमिकता देते हैं। ईईजेड नियम न केवल गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि मूल्यवर्धन, पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन पर जोर देकर समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने में भी योगदान देंगे। इस पहल से आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा मातृ-और-शिशु पोत अवधारणा की शुरुआत के माध्यम से भारतीय समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए नए क्षितिज खुलने की संभावना है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के प्रभावी निगरानी व्यवस्था के अंतर्गत समुद्र के बीच में ट्रांसशिपमेंट की अनुमति मिलती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों में, जो भारत के ईईजेड क्षेत्र का 49 प्रतिशत हिस्सा हैं, विशाल और छोटे जहाजों के उपयोग से उच्च गुणवत्ता वाली मछली के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

व्यापक सहायता और क्षमता निर्माण

सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दौरों और प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों/एफएफपीओ को व्यापक सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आसान और किफायती ऋण तक पहुँच को सुगम बनाया जाएगा।

हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाना, टिकाऊ मत्स्य पालन और समुद्री कृषि को प्रोत्साहन देना

ईईजेड नियम समुद्री इकोसिस्टम की रक्षा और मछली पकड़ने के समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए एलईडी लाइट फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग और बुल ट्रॉलिंग जैसी हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं के खिलाफकड़ा रुख अपनाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, मछली प्रजातियों के लिए एक न्यूनतम कानूनी आकार भी निर्धारित किया जाएगा और घटते मछली भंडार को बहाल करने के लिए राज्य सरकारों सहित हितधारकों के परामर्श से मत्स्य प्रबंधन योजनाएँ विकसित की जाएंगी। पर्यावरणीय अखंडता से समझौता किए बिना उत्पादन बढ़ाते हुए निकटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने के दबाव को कम करने के लिए समुद्री पिंजरे की खेती और समुद्री शैवाल की खेती जैसी समुद्री कृषि प्रथाओं को भी वैकल्पिक आजीविका के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ये उपाय विशेष रूप से छोटे पैमाने के मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों को लाभान्वित करेंगे, जिससे उन्हें गहरे समुद्र के संसाधनों तक पहुँचने, अधिक आय अर्जित करने और टूना जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों को वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में सहायता मिलेगी।

ईईजेड संचालन के लिए डिजिटल और पारदर्शी एक्सेस पास व्यवस्था - ईईजेड नियमों के अंतर्गत, मशीनीकृत और बड़े आकार के मोटर चालित जहाजों के लिए एक्सेस पास आवश्यक है, जिसे ऑनलाइन रीएएलसीराफ्ट पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। मोटर चालित या गैर-मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों का संचालन करने वाले पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों को एक्सेस पास प्राप्त करने से छूट दी गई है। यह प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल और समयबद्ध है, जिससे नाव मालिक न्यूनतम दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं, वास्तविक समय में आवेदनों की निगरानी कर सकते हैं और किसी भी कार्यालय में जाए बिना आसानी से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी होती है और समय की बचत होती है।

छोटे पैमाने के मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए, किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत, मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों को भारत के ईईजेड में संचालन के लिए एक्सेस पास प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। रीएएलसीराफ्ट को मछली पकड़ने और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है, जो प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में समुद्री भोजन के निर्यात के लिए प्रमुख आवश्यकताएं हैं। यह एकीकृत डिजिटल प्रणाली संपूर्ण निगरानी, स्वच्छता अनुपालन और इको-लेबलिंग सुनिश्चित करती है, जिससे भारतीय समुद्री उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ती है।

नियामक सुधार, समुद्री सुरक्षा और तटीय सुरक्षा

ये नियम महत्वपूर्ण सुधार ला रहे हैं ताकि भारतीय ईईजेड से उत्पन्न मत्स्य संसाधनों को राजस्व और सीमा शुल्क मानदंडों के अंतर्गत 'भारतीय मूल' के रूप में मान्यता दी जा सके, ताकि भारतीय बंदरगाह पर उतरते समय इसे 'आयात' न माना जाए और अन्य देशों को निर्यात करते समय इसे भारतीय राजकोष में विधिवत रूप से दर्ज किया जा सके। इसके अतिरिक्त, छोटे पैमाने के मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए, ये नियम भारतीय ईईजेड में अवैध मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने के लिए अवैध, बिना सूचित और अनियमित (आईयूयू) मत्स्य पालन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान करते हैं।

ट्रांसपोंडर के अनिवार्य उपयोग के माध्यम से, गहरे समुद्र में मछुआरों और मछली पकड़ने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड/मछुआरे के पहचान पत्र के अनिवार्य उपयोग के माध्यम से मछुआरों और मछली पकड़ने वाले जहाजों की पहचान सुनिश्चित की जाती है। रीअलक्राफ्ट एप्लिकेशन को नभमित्र एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया गया है जिसका उपयोग मछुआरों द्वारा सुरक्षित नेविगेशन और ट्रांसपोंडर के संचालन के लिए किया जा रहा है। इससे भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना सहित समुद्री प्रवर्तन एजेंसियों को तटीय सुरक्षा पहलू को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सामूहिक रूप से, ये सुधार भारत के समुद्री मत्स्य पालन प्रशासन के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समावेशिता के माध्यम से तटीय समुदायों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होंगे। डिजिटल नवाचार को समुदाय-आधारित मॉडलों के साथ जोड़कर, यह ढाँचा न केवल स्थायी मत्स्य पालन प्रथाओं को मज़बूत करता है, बल्कि वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार में भारत की स्थिति को भी मज़बूत करता है।

ईडी ने आम लोगों को दी चेतावनी, 7 साल तक की जेल के अलावा संपत्ति भी हो सकती है कुर्क

नई दिल्ली संवाददाता।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आम नागरिकों को चेताया है कि ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए में शामिल होने, उसका प्रचार करने या इसमें निवेश करने से बचें। एजेंसी ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ न सिर्फ भारी आर्थिक नुक़सान की वजह बनती हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैर-कानूनी कामों को बढ़ावा देती हैं; उल्लंघन की स्थिति में गिरफ़्तारी, जाँच, बैंक खातों पर रोक और संपत्ति कुर्क जैसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ईडी ने देश के आम लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए के प्रचार या निवेश से दूर रहने की सलाह दी है। ईडी ने कहा है कि गैर-कानूनी सट्टेबाजी और जुआ न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं। ईडी ने आम लोगों को दी सलाह में क्या कहा है अपने बैंक खाते, डेबिट कार्ड, PI ID या वॉलेट किसी और को इस्तेमाल करने न दें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले हाई रिटर्न या पैसिव इनकम वाले लिंक पर क्लिक न करें। किसी भी टेलीग्राम या वॉट्सऐप ग्रुप में शामिल न हों जो सट्टेबाजी या जुए का प्रचार करते हैं। अगर कोई जान-बूझकर ऐसी गतिविधि में शामिल पाया गया, तो PMLA कानून के तहत 7 साल तक की जेल और संपत्ति जब्ती हो सकती है। अगर आपको लगे कि आपका खाता गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो तुरंत बैंक और पुलिस को सूचित करें।

राज्यों और उद्योग भागीदारों ने शासन, शिक्षा और वित्त में डिजीलॉकर के स्केलेबल उपयोग-मामलों को प्रदर्शित किया

पीआईबी

इस सप्ताह नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजीलॉकर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका विषय था - 'डिजीलॉकर-सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना'। इस सम्मेलन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और डिजिटल गवर्नेंस विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन में पेपरलेस गवर्नेंस, समावेशी शिक्षा और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में डिजीलॉकर की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल दिया गया, जो देश में हो रही डिजिटल ट्रस्ट क्रांति में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने भारत मंडपम में इसका आयोजन किया। इस सम्मेलन ने सहयोगी मंच प्रदान किया ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके और दिखाया जा सके कि डिजीलॉकर कैसे एक साधारण सुरक्षित दस्तावेज़ भंडारण सुविधा से सरकार, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों में विश्वास, सुविधा और दक्षता की आधारशिला के रूप में विकसित हो रहा है।

राष्ट्रीय डिजीलॉकर सम्मेलन की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव श्री एस. कृष्णन ने की। मुख्य भाषण में श्री कृष्णन ने भारत की डिजिटल यात्रा की जानकारी दी। यह कनेक्टिविटी से क्षमता, सर्विस डिलीवरी से आत्मनिर्भरता और अब डिजिटलाइजेशन से भरोसे की ओर बढ़ रही है, जो गवर्नेंस का नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा, ÷डिजी लॉकर नागरिकों, मंत्रालयों और विभागों को जोड़ने वाली भरोसे की एक लेयर के रूप में काम करता है - जो सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और जवाबदेह डिजिटल गवर्नेंस को सक्षम बनाता है। हमारा विज़न ऐसा भविष्य है जहाँ हर डिजिटल इंटरैक्शन भरोसेमंद हो, हर नागरिक सशक्त हो, और हर संस्थान जवाबदेह हो।÷ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अपर सचिव श्री अभिषेक सिंह ने टेक्नोलॉजी-आधारित गवर्नेंस में भारत की यात्रा को 'डिजिटल ट्रस्ट क्रांति' बताया। उन्होंने लाखों लोगों के लिए गवर्नेंस सिस्टम में विश्वास बनाने में डिजीलॉकर की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने एआई-आधारित इंटेलिजेंस और ग्लोबल क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के साथ डिजीलॉकर के भविष्य की रूपरेखा बताई, और इसे पेपरलेस गवर्नेंस के लिए ग्लोबल मॉडल के रूप में पेश किया।

NeGD के प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री नंद कुमारम ने डिजी लॉकर के सुरक्षित डॉक्यूमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म से डिजिटल इंडिया के मुख्य स्तंभ के रूप में विकसित होने की जानकारी दी। यह नागरिकों को आईडी, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल और सर्टिफिकेट को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने, वेरिफाई करने और शेयर करने में सक्षम बनाता है। श्री नंद कुमारम ने कहा, ÷यह प्लेटफॉर्म गवर्नेंस के प्रति भारत के सहयोगी दृष्टिकोण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा हर नागरिक को दिए जाने वाले भरोसे और सुविधा को दर्शाता है।÷

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में 16 डीपीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे

पीआईबी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। उन्होंने वर्ष 2025 को 'सुधारों का वर्ष' घोषित करते हुए डीपीएसयू से नई प्रौद्योगिकियों के विकास, निर्यात वृद्धि और स्वदेशीकरण को गति देने पर विशेष जोर दिया था। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू को अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने और नवाचार के लिए श्रमबल को सशक्त बनाने का आह्वान किया।

सभी डीपीएसयू ने इस सिलसिले में आगामी पांच वर्षों के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास रोडमैप तैयार कर लिए हैं। पिछले दस वर्षों में, 16 डीपीएसयू ने अनुसंधान एवं विकास में कुल 30,952 करोड़ रूपये का निवेश किया है। अब अगले पांच वर्षों में 32,766 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय के साथ अनुसंधान एवं विकास की गति को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां पहले के दशक में अधिकांश निवेश पारंपरिक डीपीएसयू विशेष रूप से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा किया गया था, वहीं अब अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान सभी डीपीएसयू में समान रूप से केंद्रित हो गया है। आगामी पांच वर्षों में, आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण से गठित सात नए डीपीएसयू अनुसंधान एवं विकास में 3,000 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करेंगे, जबकि रक्षा शिपयार्ड भी 1,300 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश की योजना बना रहे हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान पिछले दस वर्षों में पूर्ण की गई विकास एवं अनुसंधान परियोजनाओं का संकलन प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही आगामी पांच वर्षों के लिए तैयार की गई नई कार्ययोजना भी जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई अनुसंधान एवं विकास नियमावली का अनावरण किया जाएगा, जो इन प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन, तेजी, जोखिम मूल्यांकन और संसाधन आवंटन की दक्षता सुनिश्चित करेगी।

रक्षा मंत्री 'स्वयं' शीर्षक से अक्षय ऊर्जा पर एक विशेष रिपोर्ट भी जारी करेंगे। यह रिपोर्ट रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में तैयार की गई है और इसमें सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा अपनाई गई ऊर्जा दक्षता एवं अक्षय ऊर्जा से संबंधित सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का व्यापक संकलन प्रस्तुत किया गया है।

उल्लेखनीय रूप से, वर्ष 2024-25 में डीपीएसयू का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इस अवधि में डीपीएसयू ने कुल 1.08 लाख करोड़ रूपये का कारोबार दर्ज किया, जो 2023-24 की तुलना में 15.4त्न की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही, कर-पश्चात लाभ बढ़कर 20,021 करोड़ रूपये हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.5त्न अधिक है। विशेष रूप से, 2024-25 में डीपीएसयू के निर्यात में 51% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता का प्रमाण है। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए डीपीएसयू को सम्मानित किया जाएगा तथा महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान होगा, जिससे रक्षा उद्योग में सहयोग एवं नवाचार को और अधिक बल मिलेगा।

भूमि संसाधन विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के दौरान योग, मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला और साइबर सुरक्षा जागरूकता का आयोजन किया।

पीआईबी

सचिव (एलआर) के मार्गदर्शन में, विशेष अभियान 5.0 की प्रगति की बारीकी से निगरानी की गई, जिससे विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में गति सुनिश्चित हुई। नोडल अधिकारी और टीम के सदस्यों ने विभाग के रिकॉर्ड रूम सहित सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस अवधि के दौरान, भूमि संसाधन विभाग ने निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य हासिल किए:

अपने परिसर में शत-प्रतिशत स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक क्रियान्वित।

लोक शिकायतों का शत-प्रतिशत निपटान।

रिकॉर्डिंग/निराई/समापन के लिए 2415 फाइलों (भौतिक फाइलें और ई-फाइलें) की समीक्षा की गई।

विशेष अभियान 5.0 के हिस्से के रूप में स्वच्छता और इसके प्रति जागरूकता के लिए विभाग द्वारा कई गतिविधियाँ की गईं। महीने के दौरान योग और मानसिक स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। अभियान अवधि के दौरान कर्मचारियों के लिए स्वच्छता गतिविधियों पर नारा लेखन, वाद-विवाद और चित्रकारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भूमि संसाधन विभाग ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ ार्मों के माध्यम से अभियान का प्रचार-प्रसार किया।

नई दिल्ली के यशोभूमि में राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन

डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी) अर्बन इन्वेस्ट विंडो (यूआईडब्ल्यूआईएन) सहित प्रमुख पहलों को लॉन्च किया

पीआईबी

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय सम्मेलन नीति निर्माताओं, शहरी योजनाकारों, विशेषज्ञों और हितधारकों सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों को छह विषयगत क्षेत्रों में गहन विचार-मंथन सत्रों के माध्यम से ÷सतत शहरी विकास और शासन÷ थीम पर विचार-विमर्श करने के लिए एकजुट करता है।

'विकसित भारत सिटी' प्रदर्शनी केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर 'विकसित भारत सिटी' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो वास्तविक रूप से विकसित, जीवंत, समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार भारतीय शहर के विजन को जीवंत करती है। यह प्रदर्शनी भारतीय शहरों में लागू किए जा रहे अभिनव शहरी नियोजन मॉडल, स्मार्ट प्रौद्योगिकीयों और लोक-केंद्रित अवसंरचना को प्रदर्शित करती है।

श्री धर का संबोधन

लोक नीति विशेषज्ञ श्री देवाशीष धर ने भारत के शहरी अवसरों की पड़ताल करते हुए, इस बात पर बल दिया कि शहर समृद्धि के स्थानिक इंजन हैं, जहां लोग विकास, अवसर और स्वतंत्रता की खोज में प्रवास करते हैं। उन्होंने शहरों को ÷श्रम बाज़ार÷ बताया, जो भीड़भाड़ और लोगों के समूहों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा और मूल डीपीआई - ÷वांछित सार्वजनिक अवसंरचना÷ के रूप में, जिस पर समृद्धि का निर्माण होता है, से आकार लेते हैं।

एनएचपीसी ने मनाया 51वाँ स्थापना दिवस

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को हर घर पहुंचाकर जनआंदोलन बनाएगी भाजपा - चंदेल

भाजपा कार्यकर्ता हर घर पहुंचकर मतदाता सूची के नामों का दो बार मिलान अवश्य करे

जांजगीर चांपा / भाजपा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) को जनआंदोलन के रूप में चलाने का आह्वान किया है। जांजगीर स्थित भाजपा कार्यालय शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में पार्टी ने जनता की एसआइआर प्रक्रिया में मदद करने और कांग्रेस पर प्रहार की करने की रणनीति तय की और जिला स्तर पर प्रभारियों व संयोजकों की नियुक्ति की हैं। कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार के नाम का दो बार मिलान करना होगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि एसआइआर अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं की भूमिका पहले की तरह निर्णायक रहेगी और इसके जरिए बूथ समितियों को और सशक्त बनाया जाएगा।

इस दौरान श्री नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस के दुष्प्रचार के बीच भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी हो। उन्होंने कहा – ÷कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रहितों का विरोध किया है और फर्जी मतदान को बढ़ावा दिया है। अब भाजपा का लक्ष्य है कि इस अभियान के माध्यम से ऐसे फर्जी मतदाताओं को चिन्हित कर रोका जाए इस कार्यक्रम की मंडल स्तर तक हमको साप्ताहिक समीक्षा करनी होगी आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रम की राजनीति को बढ़ावा दिया, जबकि यह अभियान देश को मजबूत बनाने वाला कदम है।

प्रदेश सोशल मीडिया भाजपा के पूर्व प्रभारी व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रशांत सिंह ठाकुर ने जांजगीर चाम्पा विधानसभा स्तरीय कार्यशाला मे उपस्थित कार्यकर्ताओ को सम्बोधित करते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम मे हमारे कार्यकर्ताओ की भूमिका अहम होगी सोशल मीडिया मे किस प्रकार उक्त विषय को प्रचारित किया जाए उसमे किस प्रकार का सकारात्मक पोस्ट डाला जाए जिससे आम जनमानस मे जागरुकता आए जिससे उन तक तक सही जानकारी पहुंचे हमारे कार्यकर्ता उसी विषय को सोशल मीडिया मे पोस्ट करे जिसकी उनको पुरी जानकारी हो कार्यकर्ता भ्रामक प्रचार-प्रसार से बचे क्योंकि सोशल मीडीया चलाने वाले लोगो को हमको इसकी शत प्रतिशत सही जानकारी देना ही हमारा प्रथम लक्ष्य होगा ।

उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला मे प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रशांत सिंह ठाकुर नगर पालिका , अध्यक्ष रेखा गढ़वाल , नवागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष अर्चना देवांगन , जिला उपाध्यक्ष आशुतोष गोस्वामी , पंकज अग्रवाल , कार्यक्रम के जिला प्रभारी विकास शर्मा , अमर सुल्तानिया , विवेका गोपाल , जिला मंत्री संतोषी दुबे , मंडल अध्यक्ष हितेश यादव , ध्वजाराम साहु , समर्थ सिंह , संतोष थवाईत सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

जिले में सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत कार्य प्रारंभ

274.40 किलोमीटर मार्गों की मरम्मत हेतु 575.20 लाख रुपए स्वीकृत

जांजगीर-चांपा / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं मंत्री, लोक निर्माण विभाग श्री अरूण साव ने अपने जांजगीर प्रवास दिनांक 07.10.2025 के दौरान घोषणा की गई थी कि वर्षा ऋतु पश्चात जिले की सड़कों के रख-रखाव व मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर किए जाएंगे।

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग श्रीमती ममता पटेल ने बताया उक्त घोषणा के अनुरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान हुई सड़कों की क्षति का विस्तृत सर्वेक्षण कर मूल्यांकन किया गया। खराब सड़कों को चिन्हांकित करते हुए मरम्मत हेतु आवश्यक राशि का आकलन कर लगभग 274.40 किलोमीटर लंबाई के मार्गों की मरम्मत के लिए राशि 575.20 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

विभागीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात लोक निर्माण विभाग द्वारा निविदा आमंत्रण एवं कार्यादेश जारी कर मार्गों पर मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। चिन्हांकित सभी सड़कों के मरम्मत कार्य को 31 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस निर्णय से जिले की ग्रामीण एवं शहरी सड़कों पर आवागमन सुगम होगा तथा नागरिकों को राहत मिलेगी। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने निर्देश दिए है कि मरम्मत कार्य की गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी स्थिति में कार्य की गुणवत्ता से समझौता न हो और सभी मार्गों का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें । अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने निर्देश दिए है।

अर्मान ताम्रकार ने अंतरराष्ट्रीय कराटे टीम में पाया जगह

जांजगीर चांपा /

लायंस इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, चांपा के कक्षा 9वीं के छात्र अर्मान ताम्रकार ने कराटे के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने शोतोकान फाउंडेशन द्वारा आयोजित कराटे सेल्फ डिफेंस न्यू डैन परीक्षा और स्टैमिना टेस्ट उत्तीर्ण कर अंतरराष्ट्रीय कराटे टीम में स्थान प्राप्त किया है। अब अर्मान नेपाल के हंग्सु कराटे स्टेडियम में होने वाले अंतरराष्ट्रीय कराटे चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

विद्यालय के प्राचार्य, प्रबंधन और शिक्षकों ने अर्मान की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दीं। लायन रामप्रपन्न देवांगन, अध्यक्ष (चेयरमैन) और लायन संतोष सोनी, अध्यक्ष लायंस क्लब चांपा ने कहा कि ÷अर्मान ने अपने परिश्रम और लगन से चांपा और विद्यालय का नाम रोशन किया है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है।÷ अर्मान ने कहा, ÷मैं अपने गुरुओं, माता-पिता और साथियों का आभारी हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं देश और अपने विद्यालय का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊँचा करूँ।

कलेक्टर महोबे की अध्यक्षता में गोधाम योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं विकासखंड स्तरीय समिति की बैठक आयोजित

जांजगीर-चांपा /

निराश्रित, घुमंतू तथा कृषिक पशुओं के परिरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौवंश पशु परिरक्षण अधिनियम अंतर्गत गोधाम योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य गौवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं विस्थापन के लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

जिले में स्थित गौठानों में गोधाम संचालन हेतु पंजीकृत गौशाला संचालकों, स्व-सहायता समूहों, सहकारी समितियों आदि के द्वारा आवेदन पशुधन विकास विभाग में प्रस्तुत किए गए हैं।

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में गोधाम योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति एवं विकासखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर महोबे ने जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों की समुचित जाँच के निर्देश दिए तथा गोधाम स्थापना की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ गोधाम की नितांत आवश्यकता है तथा जो गौठान नेशनल हाइवे से सटे हैं, वहाँ गोधाम स्थापना को प्राथमिकता दी जाए।

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि विकासखंड समितियों से प्राप्त आवेदनों की अनुशंसा शीघ्र की जाए, ताकि जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को अनुमोदन हेतु शीघ्र भेजे जा सकें।

बैठक में उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ जांजगीर ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर कुल 65 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 32 आवेदनों की अनुशंसा विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा की गई है।बैठक में जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, विकासखंड स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ जांजगीर उपस्थित रहे।

खाली हाथ आना, खाली हाथ जाना- सियाराम शरण दास

इस संसार में समय से बढ़कर महत्वपूर्ण वस्तु कुछ भी नहीं है

संवाददाता। जो गुरु के चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करता है, वह संसार के समस्त वैभव को अपने वश में कर लेता है। यहां तक की परमात्मा की भी प्राप्ति कर लेता है, परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर वैभव इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता!* यह बातें व्यास पीठ की आसंदी से अनंतश्री विभूषित श्री स्वामी सियाराम शरण दास जी महाराज ने श्री दूधाधारी मठ सत्संग भवन रायपुर में श्रोताओं को श्रीराम कथा का रसपान कराते हुए उद्धृत किया। उन्होंने कहा कि- *जब मन में अभिमान आते हैं तो भगवान चले जाते हैं। ईश्वर को अभिमान से द्वेष हो जाता है, उसे तो दिनता प्रिय है।* -तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीझ।। यहां राम कथा में कोई उल्टा बैठा है या सीधा बैठा है इसका महत्व नहीं है महत्व इस बात का है कि वह राम कथा में उपस्थित हुआ है। *समय से बाढ़कर ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता*। जीवन के बीते हुए क्षण को करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर भी नहीं खरीदा जा सकता इसलिए भजन करने वाले को अपने समय के एक-एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। हम कब मर जायेंगे ? कोई नहीं जान सकता! कुछ भी साथ नहीं जाएगा? *खाली हाथ आना खाली हाथ जाना। इस जीवन का क्या ठिकाना ? राम ना बिसार, बंदे राम ना बिसार* अर्थात भगवान राम के नाम का चिंतन प्रतिक्षण करना चाहिए। *श्री रामचरितमानस में नारी जाति का जितना सम्मान हुआ है, उतना संसार के किसी ग्रंथ में नहीं। जिन मूर्खों ने इसका विधिवत अध्ययन नहीं किया है वे ही इसकी निंदा करते हैं* उन्होंने कहा कि -अरे मन तू राम का भजन क्यों नहीं करता ? *यह कलि काल मलायतन। मन करि देखु बिचार।। श्री रघुनाथ नाम ताजि। नाहिन आन आधार।।* संगीतमय श्रीराम कथा में जैतू साव मठ पुरानी बस्ती रायपुर, नागरी दास मंदिर, महामाया मंदिर, बीरंचीनारायण मंदिर, राजीव लोचन ट्रस्ट कमेटी राजिम सहित शहर एवं आसपास के क्षेत्र के आध्यात्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए पदाधिकारी एवं सदस्य गण बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मरीजों से सीधे संवाद कर ली मिल रही स्वास्थ्य

निर्माण एजेंसी की धीमी गति पर जताई नाराज़गी, कार्य समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश

डॉक्टरों को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ देने के निर्देश

जांजगीर-चांपा /

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की बेहतर स्वास्थ सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज जिला चिकित्सालय जांजगीर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपातकालीन कक्ष, लेबर वार्ड, डायलिसिस यूनिट, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी कक्ष, नेत्र विभाग, दवा वितरण कक्ष और आर्थो वार्ड का गहन निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर महोबे ने मरीजों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य परीक्षण कराने आए नागरिकों से सीधे संवाद कर सेवाओं की उपलब्धता और सुविधाओं की जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि साफ-सफाई में किसी भी स्तर पर कमी ना हो। निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सोनोग्राफी कक्ष में तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश - निरीक्षण के दौरान एक महिला मरीज ने कलेक्टर को बताया कि सोनोग्राफी रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर कलेक्टर महोबे ने तत्काल सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराई जाए और आगे की जाँच एवं उपचार में देरी न हो। उन्होंने कहा कि सोनोग्राफी यूनिट में किसी भी प्रकार की तकनीकी दिक्कत न आए, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

शिशु वार्ड में वेंटिलेटर क्षमता बढ़ाने और आवश्यक स्टाफकी भर्ती का प्रस्ताव भेजने के निर्देश – कलेक्टर महोबे ने नवजात शिशु वार्ड का निरीक्षण करते हुए वेंटिलेटर, उपकरणों और स्टाफ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि शिशु वार्ड में वेंटिलेटर की क्षमता बढ़ाने और चिकित्सालय में आवश्यक प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित के लिए प्रस्ताव भेजने कहा ।

एनआरसी में बच्चों व माताओं के लिए बेहतर पोषण व मनोरंजन की व्यवस्था के निर्देश

निरीक्षण के दौरान उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) का भी निरीक्षण किया और वहाँ भर्ती बच्चों एवं माताओं से संवाद किया। उन्होंने कुछ माताएँ जो एनीमिक की समस्या से ग्रस्त हैं, उनके लिए उचित उपचार और प्रोटीनयुक्त भोजन की व्यवस्था की जाए।कलेक्टर महोबे ने एनआरसी हॉल में बच्चों के खेलने हेतु अधिक स्पेस, खेल सामग्री और मनोरंजन साधन की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए।उन्होंने माताओं को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आहार में प्रोटीन, हरी सब्जियाँ शामिल हों।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर महोबे ने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति की जाँच की और समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. एस. कुजुर सहित जिला चिकित्सालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

इंडिजेनस जस्टिस एवं विधिक जागरूकता पर क्षेत्रीय भ्रमण एवं कार्यशाला

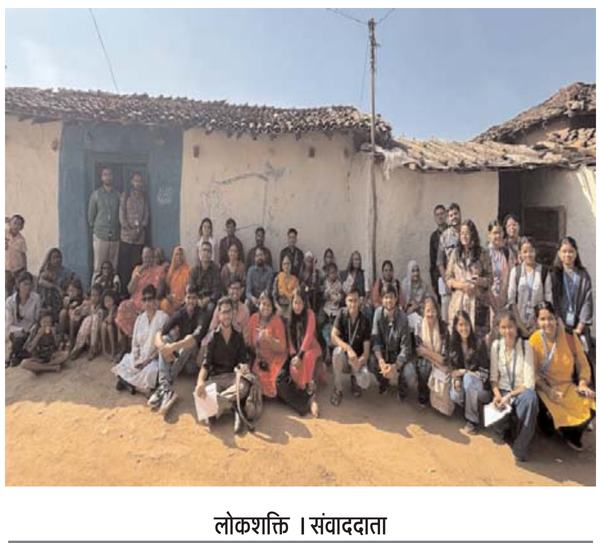

लोकशक्ति ।संवाददाता

विधि सहायता एवं सामाजिक सेवा समिति (स्र्स्ष्ट ।।ह्रु) और सेंटर फॉर लॉ एंड इंडिजेनस स्टडीज, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (ष्ठस्रु), महासमुंद और निर्मया कैंसर फाउंडेशन, रायपुर के सहयोग से 5 नवंबर 2025 को बोरिद गाँव, जिला महासमुंद में इंडिजेनस न्याय एवं विधिक जागरूकता विषय पर एक क्षेत्रीय भ्रमण एवं कार्यशाला का आयोजन किया। कुल 34 छात्र स्वयंसेवक और पांच शिक्षण संकाय सदस्य, डॉ. कौमुदी छल्ला, डॉ. अयान हाजरा, डॉ. अर्चना श्याम घरोटे, श्री प्रदीप बर्मन और श्री दीपक कुमार ने क्षेत्रीय दौरे में भाग लिया, उनके साथ निर्मया कैंसर फाउंडेशन से सुश्री सुदेशना और एडवोकेट संजीव कुमार पांडा, उप प्रमुख कानूनी और रक्षा परिषद प्रणाली और डीएलएसए, महासमुंद से एडवोकेट डोला मणि पटेल भी थे।

एचएनएलयू के माननीय कुलपति प्रो. डॉ. वी. सी. विवेकानंदन ने कहा कि इस तरह के क्षेत्रीय दौरे और कार्यशालाएं विधि छात्रों को आदिवासी समुदायों के सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक ताने-बाने से परिचित कराएंगी और समाज की वास्तविकताओं के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी और उन्हें देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने में मदद करेंगी।

टीम सुबह 8 बजे विश्वविद्यालय परिसर से रवाना हुई और सुबह 11 बजे तक रायपुर से लगभग 83 किलोमीटर दूर ग्राम बोरिद पहुँची। टीम के सदस्यों ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण का पहला चरण शुरू किया और गाँव के परिवारों से मिलकर उनके सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थितियों को समझा।

खास खबर

बिजली दर वृद्धि के खिलाफ आप ने किया विरोध प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी

कोरबा जिले में आम आदमी पार्टी (आप) ने बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ बालको स्थित रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने कोरबा जिला कलेक्टर/एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने मांग की गई।

आप के जिलाध्यक्ष रिचर्ड डेविड ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाजपा सरकार आम जनता की परेशानियों को नजर अंदाज कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर गलत आंकड़े पेश कर रही है और निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार कर रही है।

श्री डेविड ने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ एक बिजली सरप्लस राज्य होने के बावजूद बिजली महंगी क्यों की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार 15-20% लाइन लॉस बताती है, जबकि यह 3% से अधिक नहीं होता। साथ ही, बड़े व्यापारियों और नेताओं के करोड़ों रुपए के बिजली बिल बकाया होने के बावजूद उनसे वसूली नहीं की जा रही, बल्कि गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है।

आप के प्रदेश संगठन मंत्री आनंद सिंह ने बताया कि पार्टी लगातार इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रही है और लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। रिचर्ड डेविड ने यह भी कहा कि यह आंदोलन अभी शुरुआत है और इसे प्रदेश स्तर पर बृहद रूप दिया जाएगा।

असामयिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़, तहसील लैलूंगा के ग्राम-पिपराही निवासी संतोषी जाटवर की आग में जलने से हुई असामयिक मृत्यु होने पर एसडीएम लैलूंगा की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 की कंडिका के अंतर्गत मृतक के नजदीकी वारिसान को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

योग प्रशिक्षक व खेल शिक्षक पद के लिए आवेदन 24 तक

रायगढ़, । जिले के पीएमस्कूलों में स्वीकृत रिक्त पद-अंशकालीन योग प्रशिक्षक एवं खेल शिक्षक पद पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से 24 नवम्बर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिले के वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अवलोकन कर सकते है एवं आवेदन पत्र प्रारूप डाउनलोड कर सकते है।

आवास निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित समीक्षा करें अधिकारी: सीईओ जिला पंचायत

'मनरेगा का लेबर बजट युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से बनाएं'

'डीएमएफसे स्वीकृत कार्य एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ किए जाएं'

'मनरेगा,डीएमएफ,एनआरएलएम सहित योजनाओं की हुई समीक्षा'

कोरबा लोकशक्ति।

जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दिनेश कुमार नाग ने गुरुवार को जिला पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय योजनाओं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं डीएमएफ जिला खनिज संस्थान न्यास की गहन समीक्षा बैठक ली।

बैठक में सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ और एसडीओ को निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कार्यों की नियमित समीक्षा करें और मैदानी अमला सतत ग्राम भ्रमण कर हितग्राहियों को समय पर आवास पूर्ण करने हेतु प्रेरित करें।

उन्होंने बताया कि जिले में 14 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य दिसंबर तक पूर्ण किया जाना है, इसके लिए सभी अधिकारी कार्य में तेजी लाएं। साथ ही सीएसपीडीसीएल के समन्वय से प्रधानमंत्री जनमन आवासों में सौर ऊर्जा आपूर्ति एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित की जाए। श्री नाग ने कहा कि खनिज न्यास मद से जनहित में बड़े पैमाने पर कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे सभी अप्रारंभ कार्यों को एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ किया जाए और निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर कोरबा श्री अजीत वसंत स्वयं डीएमएफ कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, इसलिए कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने जियो टैगिंग कार्य पूर्ण करने, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रकरणों की बैंक स्वीकृति 15 दिनों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मनरेगा से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्यों को एक सप्ताह में प्रारंभ कराने तथा विभागीय जांचों को 15 दिनों में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों का प्लान तैयार कर नियमानुसार अपलोड किया जाए। साथ ही जलदूत ऐप के माध्यम से सभी कूपों का पोस्ट-मानसून माप तकनीकी सहायकों द्वारा शीघ्र पूर्ण किया जाए।

लंबित सामाजिक अंकेक्षण प्रकरणों का निराकरण एवं वसूली शीघ्र पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। सीईओ ने सभी अधिकारियों से कहा कि एरिया ऑफिसर एप में मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण कर ऐप में एंट्री सुनिश्चित करें, ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों सुनिश्चित हो सकें। बैठक में उप संचालक पंचायत, सहायक परियोजना अधिकारी,एसडीओ आरईएस, जनपद पंचायत के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी नरेगा के जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण एवं पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करें-कलेक्टर

रायगढ़, लोकशक्ति

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की त्रैमासिक बैठक आज कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष रायगढ़ में आयोजित की गई। बैठक में लैलूंगा विधायक श्रीमती विद्यावती सिदार, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, संयुक्त कलेक्टर राकेश गोलछा सहित आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में पूर्व की बैठक की कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन पेश किया गया। इसके साथ ही इस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ घटित अपराध के मामलों मे पुलिस विवेचना के लंबित प्रकरण, चालान प्रस्तुत प्रकरण, न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण, घोषित सजा एवं अपराध मुक्त वाले प्रकरणों के आँकड़े तथा पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि अत्याचार पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसा कोई प्रकरण दर्ज होते ही संवेदनशीलता के साथ पीड़ित को विधिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार पात्रता की स्थिति में पीड़ितों को आकस्मिक सहायता यथाशीघ्र प्रदान की जाए। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने कहा कि पीड़ितों का थाना से सीधा संपर्क होता है, इसलिए प्रारंभिक स्तर पर ही उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता से निराकरण किया जाए। उन्होंने अधीनस्थ अमले को निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में स्थायी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, उनमें पीड़ितों को आवेदन भरवाकर संबंधित राजस्व अधिकारी को भेजा जाए ताकि प्रमाण पत्र शीघ्र तैयार कर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। लंबित विवेचनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण कर चालान न्यायालय में शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। पुराने लंबित प्रकरणों मे न्यायालय की आवश्यक प्रक्रिया समय से पूर्ण करने के लिये शासकीय अभिभाषक को शीघ्र प्रयास करने के लिये कहा गया। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक जिले में अनुसूचित जाति के 15 नागरिकों और अनुसूचित जनजाति के 11 नागरिकों के दर्ज किए गए हैं जिनमें से कुल 21 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है जबकि शेष प्रकरण विवेचना में लंबित हैं। वर्तमान में अधिनियम अंतर्गत 77 प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन हैं। सहायक आयुक्त ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अजा और अजजा संवर्ग के जरूरतमंद एवं उत्पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करना है।

निगम आयुक्त ने की बड़ी कार्रवाई, 3 अधिकारियों को निलंबित किया

कोरबा संवाददाता।

नगर पालिक निगम कोरबा के आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने काऊ केचर में जनप्रतिनिधियों के कटआउट का परिवहन कर जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने व कार्य के प्रति घोर लापरवाही के आरोप में निगम के 02 उप अभियंताओं अश्वनी दास व अभय मिंज तथा स्वच्छता निरीक्षक सचीन्द्र थवाईत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर घंटाघर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर ओपन थियेटर स्थित मैदान में 02 से 04 नवंबर तक आयोजित हुए राज्योत्सव हेतु कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन व महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत के कटआउट लगाए जाते थे। निगम के केन्द्रीय भण्डारगृह से इन कटआउटों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने हेतु काऊकेचर वाहन का उपयोग संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया। मामला प्रकाश में आने पर निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया।

ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं का प्राचार्य पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ

बिलासपुर (संवाददाता)।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य शासन द्वारा तय किए गए प्राचार्य पदोन्नति नियमों और कैडर मापदंडों को वैध ठहराते हुए शिक्षक नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले से ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं की प्राचार्य पद पर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इससे पहले, याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने 5 अगस्त 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था। अब सिंगल बेंच ने राज्य शासन के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि 65% ई संवर्ग, 25% लोकल बॉडी संवर्ग और 10% सीधी भर्ती का कोटा पूरी तरह से उचित है।डिवीजन बेंच की जस्टिस रजनी दुबे और अमितेंद्र कुमार प्रसाद की पीठ ने पहले ही सरकार के नियमों को सही माना था। कोर्ट ने कहा कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 और प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को जारी प्राचार्य पदोन्नति सूची पर लगी रोक हटा दी है।

राज्य सरकार ने अप्रैल में 2,813 व्याख्याताओं की पदोन्नति सूची जारी की थी, जिसे लेकर कई शिक्षकों ने आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि प्राचार्य पद प्रशासनिक है, इसलिए केवल बीएड डिग्रीधारकों को ही पात्र माना जाए।

धान खरीदी के लिए संवेदनशील धान उपार्जन केन्द्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नामांकित

संवाददाता

कोरबा । कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु जिले के अति संवेदनशील एवं संवेदनशील धान उपार्जन केंद्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है।

खरीफविपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन 15 नवंबर से सहकारी समितियो के माध्यम से किया जायेगा। समिति स्तर पर धान खरीदी अवधि के दौरान जिले के अति संवेदनशील एवं संवेदनशील खरीदी केन्द्रों में प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार अति संवेदनशील धान उपार्जन केन्द्र उतरदा के लिए तहसीलदार हरदीबाजार अभिजीत राजभानू, कुल्हरिया के लिए तहसीलदार पसान विरेन्द्र कुमार और अखरापाली के लिए तहसीलदार दीपका अमित केरकेट्टा को प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है।

इसी प्रकार संवेदनशील धान उपार्जन केन्द्र भिलाईबाजार हेतु नायब तहसीलदार दीपका बंदराम भगत, कटघोरा- तहसीलदार कटघोरा सूर्यप्रकाश केषकर, सुमेधा-तहसीलदार दर्री प्रियंका चंद्रा, करतला- नायब तहसीलदार करतला देवेन्द्र कुमार, तुमान- राजस्व निरीक्षक बरपाली केषर चैहान, बरपाली (बरपाली)- तहसीलदार बरपाली सत्यपाल प्रताप राय, उमरेली- राजस्व निरीक्षक कोठारी पुरूषोत्तम धाकडे, सोहागपुर- नायब तहसीलदार बरपाली जानकी काठले, दादरखुर्द- नायब तहसीलदार कोरबा सविता सिदार, सोनपुरी- नायब तहसीलदार कोरबा दीपक पटेल, बरपाली(कोरबा)- नायब तहसीलदार भैंसमा मधुसुदन, तिलकेजा- तहसीलदार भैंसमा के.के.लहरे, भैंसमा- राजस्व निरीक्षक भैंसमा करूणा मैत्री, नोनबिर्रा- राजस्व निरीक्षक हरदीबाजार नारायण बागरी, हरदीबाजार- राजस्व निरीक्षक हरदीबाजार प्रदीप कुमार सोनी, कोरबी (पोंड़ीउपरोड़ा)- राजस्व निरीक्षक कोरबी रंजीत भगत, मोरगा- राजस्व निरीक्षक पोंड़ीउपरोड़ा मनीष जायसवाल और संवेदनशील धान उपार्जन केन्द्र सिरमिना हेतु राजस्व निरीक्षक पोंड़ी उपरोड़ा सुमनदास मानिकपुरी को प्रभारी अधिकारी नामांकित किया गया है।

धान खरीदी: उपार्जन केंद्रवार मॉनिटरिंग के लिए जिला अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

0-105 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे पंजीकृत किसान

रायगढ़, । शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 15 नवम्बर से प्रारंभ होगा। उपार्जन केंद्रवार मॉनिटरिंग और सतत निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें धान खरीदी से संबंधित सभी तकनीकी और व्यवस्थागत पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में अधिकारियों को धान उपार्जन नीति, उपार्जन केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तुंहर टोकन मोबाइल ऐप, चेक पोस्ट व्यवस्था और गुणवत्ता परीक्षण के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई।

जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने बताया कि किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 15 नवम्बर से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ (लिंकिंग सहित) निर्धारित की गई है। खरीदी प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए अब किसानों को उपार्जन केंद्रों में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों की ऋण पुस्तिका का डेटा एग्रीस्टेक पोर्टल से सीधे जुड़ा रहेगा, जिससे उनकी पहचान व पात्रता स्वतः सत्यापित हो जाएगी। इससे किसानों को सुविधा मिलेगी और खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

जिले की 69 समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। अवैध धान परिवहन पर नियंत्रण के लिए 10 अंतराज्यीय एवं 15 आंतरिक चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी के लिए तीन-तीन पालियों में चार टीमें तैनात की गई हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान, डुबान क्षेत्र, वन अधिकार पट्टा धारक और ग्राम कोटवार वर्ग के किसानों को पंजीयन से छूट दी गई है। धान विक्रय की राशि किसानों को डिजिटल माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

तुंहर टोकन ऐप से पारदर्शी और सुव्यवस्थित खरीदी प्रक्रिया

धान खरीदी को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से प्रारंभ की जाएगी। सोसायटी संचालक सुबह 9.30 बजे से टोकन जारी कर सकेंगे, जो अगले 7 खरीदी दिवसों के लिए वैध रहेंगे। प्रत्येक टोकन में धान की मात्रा पंजीकृत रकबे से अधिक नहीं होगी। लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन तथा बड़े किसानों को अधिकतम 3 टोकन जारी किए जा सकेंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है, जिससे किसान की सहमति के बिना कोई भी टोकन जारी नहीं हो सकेगा।

शिकायतों के समाधान हेतु टोल फ्री नंबर जारी धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए खाद्य विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया गया है। यह कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। सभी उपार्जन केंद्रों में इस नंबर का प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि किसान एवं संबंधित व्यक्ति आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। प्राप्त शिकायतों का निराकरण तीन दिवस के भीतर किया जाएगा।

ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भर्ती परीक्षा 9 को

रायगढ़, । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा 9 नवम्बर 2025 को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला (एचजीएमएस 25) भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम मोबा. 97535-36151 को नोडल अधिकारी एवं व्याख्याता शा.हाईस्कूल मिड़मिड़ा बाबूलाल पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

मोपेड चलाते समय डिवाइडर से टकराकर प्रतीष्ठित व्यवसायी की हुई मृत्यु

कोरबा नगर में स्कूटी चलाते समय एकाएक डिवाइडर से टकराकर नगर के प्रतीष्ठित डेयरी व्यवसायी गंभीर घायल हो गए। उन्हें चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। कोरबा शहर के सिटी कोतवाली के समीप स्थित नंदी डेयरी व दीपका में संचालित अन्नापूर्णा डेयरी के संचालक 80 वर्षीय बद्री गुप्ता घर से स्कूटी लेकर जरूरी कार्य हेतु निकले थे। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से गुजरते समय वे होटल गणेश इन् के पास स्कूटी सहित एक डिवाइडर से टकरा गए। गंभीर चोट लगने और अधिक खून बहने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें चिकित्सालय ले जाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर वैधानिक कार्रवाई की। परिजन के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों को उन्होंने अचानक चक्कर आने की वजह से स्कूटी सहित डिवाइडर से टकराना बताया था। शांत,सहज, सरल, मृदुभासी, धार्मिक प्रवित्ति के प्रतिष्ठित व्यवसायी बद्री गुप्ता की मृत्यु से परिजन, मित्रगण, रिश्तेदार, व्यापारी वर्ग सहित अंचल में शोक व्याप्त है।

गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में लाएँ गति : सीएम विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में संचालित सभी निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हों तथा निर्माण कार्यों की गति में तेजी लाई जाए।मुख्यमंत्री श्री साय ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश देते हुए कहा कि जल संसाधन परियोजनाएँ प्रदेश के सर्वांगीण विकास की धुरी हैं। उन्होंने कहा कि जनता को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई परियोजनाओं का निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी निर्माणाधीन एवं प्रगतिरत सिंचाई परियोजनाओं के कार्यों में गति लाने के स्पष्ट निर्देश दिए।

बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने मुख्यमंत्री को पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से प्रदेश की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

युवाओं के लिए रोजगार का अवसर, 12 नवंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन

0 कस्टमर केयर और सेल्स कंसल्टेंट के 180 पदों पर भर्ती

रायपुर,आरएनएस)। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर में 12 नवंबर दिन बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैम्प के लिए स्क्वायर बिज़नेस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कस्टमर केअर एग्जेक्युटिव के 150 पद एवं जी. के. ऑटो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा सेल्स कंसलटेंट के 30 रिक्त पदों की भर्ती होगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वी से स्नातक रखी गई है। इच्छुक आवेदक/आवेदिका सुबह 11 से 2 बजे तक निर्धारित स्थल पर अपनी

शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, रोजगार पंजीयन, आधारकार्ड की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साईज फ ोटोग्राफ बायोडाटा सहित उपस्थित हो सकते हैं। इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन पूर्णतः निःशुल्क है।

वन्दे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर जगदलपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन

रायपुर। वन्दे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर जगदलपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी (टाउन हॉल) में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि वन्दे मातरम् देश की आजादी की प्रेरणा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह गीत स्वर्गीय बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवम्बर 1875 को रचा गया था, जिसे बाद में उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित किया गया। इसकी प्रारंभिक पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर 7 नवम्बर से पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जगदलपुर में भी यह कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वन्दे मातरम् वर्षगांठ संबोधन के राष्ट्रीय प्रसारण से हुई, जिसे दूरदर्शन के माध्यम से सभी शासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में दिखाया गया। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई। सेजस और सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों ने वन्दे मातरम् गीत का सामूहिक गायन किया। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों और छात्र-छात्राओं द्वारा टाउन हॉल से सिटी ग्राउंड तक रैली निकाली गई।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, नगर निगम सभापति श्री खेमसिंह देवांगन, पूर्व विधायक श्री बैदूराम कश्यप, कलेक्टर श्री हरिस एस, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, आम नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय, जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालय सहित जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में वन्दे मातरम् की 150 वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया गया।

अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में जांजगीर-चांपा जिले के कातेनगर सोठी स्थित भारतीय कुष्ठ निवारक संघ को ÷यति यतनलाल सम्मान 2025÷ से सम्मानित किया गया। संस्था को यह सम्मान अहिंसा, गौरक्षा एवं मानव सेवा के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।भारतीय कुष्ठ निवारक संघ वर्षों से समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास, पशु संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा कार्य कर रहा है। संस्था द्वारा की जा रही सेवाएं पूरे राज्य के लिए प्रेरणास्रोत हैं।इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिला कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आश्रम परिवार को बधाई देते हुए कहा कि ÷यह सम्मान केवल एक संस्था का नहीं, बल्कि उन सभी सेवाभावियों का सम्मान है जो अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि जिले के लिए यह सम्मान गर्व की बात है।

वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मुख्यमंत्री 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित स्मरणोत्सव में वर्चुअली हुए शामिल

रायपुर। 'वंदे मातरम' राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज देशभर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक दिन को छत्तीसगढ़ में भी बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम' का गायन किया। इस अवसर पर सभी ने ÷वंदे मातरम÷ के उद्घोष के साथ आज़ादी की राष्ट्रीय चेतना का पुण्य स्मरण किया और अमर बलिदानियों को नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित स्मरणोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए और प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी सुना।मुख्यमंत्री 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली में आयोजित स्मरणोत्सव में वर्चुअली हुए शामिलप्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि वंदे मातरम् मां भारती की साधना और आराधना की प्रेरक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' के सामूहिक गान का एक प्रवाह, एक लय और एक तारतम्य हृदय को स्पंदित कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'वंदे मातरम' का मूल भाव मां भारती है – यह भारत की शाश्वत संकल्पना, स्वतंत्र अस्तित्व-बोध और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'वंदे मातरम' भारत की आज़ादी का उद्घोष था, जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने और स्वाधीन भारत के स्वप्न को साकार करने की प्रेरणा दी। स्वतंत्रता आंदोलन में यह गीत क्रांतिकारियों की आवाज़ बना और यह केवल प्रतिरोध का स्वर नहीं, बल्कि आत्मबल जगाने वाला मंत्र बन गया। श्री मोदी ने कहा कि 'वंदे मातरम' में भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की कहानी समाहित है। विदेशी आक्रमणों और अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों के बीच 'वंदे मातरम' ने समृद्ध भारत के स्वप्न का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत के नए स्वरूप का उदय देख रही है, जो अपनी परंपरा, आध्यात्मिकता और आधुनिकता के समन्वय से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'वंदे मातरम' आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना स्वतंत्रता संग्राम के समय था, और यह गीत सदैव हमारे हृदयों में अमर रहेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दीं और कहा कि यह गीत मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम, कृतज्ञता और राष्ट्रधर्म की भावना का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश ने एक स्वर में 'वंदे मातरम' का सामूहिक गायन कर मातृभूमि की वंदना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के वर्षभर चलने वाले स्मरणोत्सव का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रव्यापी शुभारंभ इस कालातीत रचना के 150 वर्ष पूरे होने का गौरवपूर्ण अध्याय है। इस अवसर पर वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्मारक सिक्के का जारी होना एक ऐतिहासिक स्मृति है। श्री बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम् गीत भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा रहा है, जिसने सदैव राष्ट्रीय गौरव, एकता और आत्मसम्मान की ज्योति प्रज्वलित की है। यह मातृभूमि की शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक है, साथ ही भारत की एकता और आत्मगौरव की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि 7 नवम्बर 1875 को बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने इस कालजयी रचना की सृष्टि की थी, जिसे बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंद मठ' में शामिल किया गया। मातृभूमि की स्तुति में रचा गया यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति की सबसे प्रबल प्रेरणा बना। अनेक क्रांतिकारियों ने ÷वंदे मातरम÷ कहते हुए हँसते-हँसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय 'वंदे मातरम' ने स्वदेशी आंदोलन को नई ऊर्जा दी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यह गीत सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रभक्ति का मंत्र बन गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि 'वंदे मातरम' सुनते ही हृदय में ऊर्जा, गर्व और देशभक्ति का संचार होता है। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि हमारी भूमि, जल, अन्न और संस्कृति ही हमारी जीवनदायिनी शक्ति हैं। उन्होंने कहा, ÷यूरोप में भूमि को 'फादरलैंड' कहा जाता है, लेकिन भारत में हम अपनी भूमि को 'मातृभूमि' कहते हैं।

कच्चे माइंस के बस चालक की जलकर मौत

बालोद । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कच्चे माइंस में काम करने वाले एक बस चालक ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र के नगर लोडिंग साइड की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान मिथलेश साहू के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कांकेर जिले का रहने वाला था और पिछले कई सालों से कच्चे माइंस में बस चालक के रूप में कार्यरत था। उसका काम रोजाना खदान क्षेत्र से कर्मचारियों को लाने-ले जाने का था। बताया जाता है कि घटना के दिन मिथलेश अपने घर पर अकेला था। अचानक उसने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देखा तो तुरंत घर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक मिथलेश पूरी तरह जल चुका था। परिवार के अन्य सदस्य जब पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद दल्लीराजहरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि अभी आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा चरडोंगरी, खड़ौदा खुर्द एवं रघ्घुपारा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान विभिन्न ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ आत्मीयता पूर्वक सीधे संवाद किया। इस दौरान वे ग्राम चरडोंगरी, खड़ौदा खुर्द एवं रघ्घुपारा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। जहां उन्होंने अपने सरल सहज अंदाज में लोगों से आत्मीय भेंट की।

ग्राम चरडोंगरी पहुँचकर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनके हाल-चाल जाने। उन्होंने ग्रामीणों से उनकी मांगों, समस्याओं और शिकायतों को विस्तार से सुना तथा उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार का उद्देश्य हर ग्राम तक विकास की रोशनी पहुँचाना है और शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सुनिश्चित करना है।

इसके पश्चात उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ग्राम खड़ौदा खुर्द पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वर्गीय लोकनाथ साहू के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। इसके बाद उन्होंने ग्राम रघ्घुपारा में आयोजित स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास पटेल जी के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिजनों को ढांढस बंधाया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती बालका रामकिंकर वर्मा, उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण उपस्थित थे।

जांजगीर-चांपा में उद्योग आउटरीच बैठक में ईपीएफओ ने दी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की विस्तृत जानकारी

रायपुर । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा आज जांजगीर-चांपा जिले में उद्योग संघों एवं नियोक्ताओं की उपस्थिति में उद्योग आउटरीच बैठक एवं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा के सनराइज़ हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयवदन इंगले, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-प्रथम, रायपुर ने की। उन्होंने उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों एवं नियोक्ताओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के उद्देश्य, पात्रता एवं लाभों के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विभिन्न डिजिटल सेवाओं की जानकारी विस्तारपूर्वक प्रदान की। इंगले ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों को प्रोत्साहन लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही, ईडीएलआई के माध्यम से पूर्व में अपंजीकृत कर्मचारियों को पंजीकृत कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाने की दिशा में संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में कोसा,

सिल्क, इस्पात, निर्माण एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों एवं नियोक्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक के पश्चात ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा कोसा सिल्क उत्पादन इकाई का भ्रमण किया गया, जहां श्रमिकों को भविष्य निधि से संबंधित जानकारी दी गई और उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन किया गया। यह आयोजन उद्योग जगत और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मध्य सहयोग, संवाद और विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिससे क्षेत्र में रोजगार संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता को नई दिशा प्रदान की।

प्रमुख सचिव श्री सोनमणी बोरा ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा

जनजातीय गौरव दिवस एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणी बोरा ने आज बिलासपुर जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बिलासपुर संभाग सहित कुल 10 जिलों बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, मुंगेली, कबीरधाम, रायगढ़ एवं कोरबा के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ, संबंधित सहायक आयुक्त एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे। श्री बोरा ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय योजनाओं की निगरानी नियमित समीक्षा एवं फील्ड निरीक्षण के माध्यम से की जाए। उन्होंने अधिकारियों से जनजातीय समुदाय के बीच जाकर योजनाओं की जानकारी देने, संपर्क एवं संवाद बढ़ाने पर भी बल दिया। शासन की योजनाओं का लाभ तभी सार्थक होगा जब वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। सभी अधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अपूर्ण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि जो कार्य नियोजित अवधि में पूर्ण नहीं किए जा सकते, उन्हें निरस्त किया जाए, और जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनके उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) तत्काल प्रस्तुत किए जाएँ। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएँ सीधे जनहित से जुड़ी हैं, अतः इनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रमुख सचिव ने बताया कि 15 नवम्बर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपरा और संस्कृति के संरक्षण हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि बिलासपुर जिले में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सम्मिलित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दिन सभी आश्रमों और छात्रावासों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम 19 एवं 20 नवम्बर को अंबिकापुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आगमन की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा।

खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लाखों की ठगी,आरोपी गिरफ्तार

खैरागढ़ । जिले में खुद को थाना प्रभारी बताकर कई लोगों से लाखों रुपये ठगने वाले एक फर्जी पुलिसकर्मी को छुईखदान पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम छिंदारी निवासी सुखऊ राम नेताम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गुसेश्वर तिवारी उर्फ जीपी पांडे नामक व्यक्ति जो कि खुद को पुलिस का अधिकारी बताता था और पुलिस की वर्दी में घूमता था उसने उनके रिश्तेदार धनेश्वर नेताम को पुलिस में भर्ती कराने का भरोसा दिलाया और इसके बदले कुल 1 लाख 6 हजार रुपये ले लिये और नौकरी नहीं लगाई। शिकायत मिलते ही छुईखदान थाना प्रभारी और सायबर सेल की संयुक्त टीम सक्रिय हो गई। टीम ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसके आने-जाने के रूट की जानकारी जुटाई। योजनाबद्ध तरीके से की गई घेराबंदी के दौरान आरोपी को छुईखदान क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने पहले भी बोरतालाब और मोहगांव क्षेत्र में इसी तरह लोगों को नौकरी का झांसा देकर ठगा है। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली, तो खाकी और कॉम्बैट वर्दी, तीन स्टार वाले फ्लैप, जीपी तिवारी के नाम की नेमप्लेट, छत्तीसगढ़ पुलिस का मोनो, बेल्ट, लेनयार्ड, मोबाइल फोन और नकद राशि मिली। इन सभी वस्तुओं से यह साफ था कि आरोपी ने अपनी फर्जी पहचान को असली दिखाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल सलोनी भेज दिया गया।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राइवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)